सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 14 जुलाई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 312, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

इतिहास इंतजार करने वाली सेनाओं का साथ नहीं देता...

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

भारतीय सेना ने आजादी के बाद अपने सबसे महत्वाकांक्षी संरचनात्मक तथा संगठनात्मक सुधार को लागू करते हुए अभी 1 जुलाई को अपने 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (IBG) (एकीकृत युद्ध समूहों) को प्रस्तुत किया। लेकिन इसके साथ एक असुविधाजनक सवाल भी उभराः भावी युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही सेना के लिए जिस सुधार की जरूरत 2002 में ही मान्य की जा चुकी थी और जिसकी संकल्पना 2018 में ही तय की जा चुकी थी उस सुधार को लागू करने में क्या 10 साल और लगाए जा सकते हैं?

बहरहाल, सुधार को संकल्पना पत्र से निश्चित ही आगे बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले चरण में अगले दो साल में, XVII माउंटेन स्ट्राइक कोर के दो डिवीजनों को पांच IBG और एक फायर सपोर्ट ग्रुप (कोर के स्तर पर) में बदल दिया जाएगा। सुधरे हुए मॉडल को सेना की 42 इन्फैन्ट्री, माउंटेन, रैपिड, आर्मर्ड, और आर्टिलरी डिवीजनों, और 12 आर्मर्ड/ इन्फैन्ट्री ब्रिगेडों पर लागू किया जाएगा।

लेकिन, IBG का गठन पुनर्गठन की लंबी प्रक्रिया में नहीं तब्दील होनी चाहिए। यह भारतीय सेना के भावी रणक्षेत्र की तकनीकी धुरी बननी चाहिए। और यह काम अगले पांच वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए।

IBG की जड़ें ऑपरेशन संबंधी बुनियादी समस्या में पाई जाती हैं। दो सदियों से, पारंपरिक कंबाइंड-आर्म्स डिवीजन ही सेनाओं के युद्ध लड़ने वाले पूर्वनिर्धारित समूह रहे हैं। इनमें सैनिकों की बड़ी संख्या की, हेडक्वार्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले अभियान के लिए तैनात किया जाता है, जबकि भावी युद्ध में समय की कमी पड़ने वाली है। ऑपरेशनों के लिए डिवीजनों के संसाधनों से ही तैयार किए जाने वाले ब्रिगेड बैटल ग्रुप्स में संगठनात्मक एकजुटता का अभाव होता है।

भारतीय सेना ने यह सबक 2001-02 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान काफी कष्ट से सीखा, जब उसने सक्रिय होने में तीन सप्ताह लगा दिए थे और पाकिस्तान के खिलाफ पहल करने का मौका और बढ़त गंवा दी थी। इसके बाद 2003-04 से, सेना ने डिवीजन के आकार के बैटल ग्रुप्स के बूते काम करना शुरू कर दिया। इन्हें युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन की आक्रामक, 'कोल्ड स्टार्ट' रणनीति को लागू करने के लिए उतारने की योजना थी।

लेकिन इन बैटल ग्रुप्स का आकार भी काफी बड़ा था और इन्हें धीरे-धीरे ही सक्रिय किया जा सकता था। 2018 में, जनरल बिपिन रावत ने चुनौती का सीधा सामना किया और उभरते IBG का विस्तृत अध्ययन करने का आदेश दिया। 2019 में, मैदानी इलाके में 9 कोर में और पहाड़ी इलाके में 17 कोर में IBG के साथ प्रयोगात्मक फील्ड अभ्यास किए गए ताकि संकल्पना का परीक्षण हो और उसमें सुधार किया जाए।

IBG के गठन में तेजी लाने का एक कारण यह भी है कि भारत और इसके प्रतिद्वंद्वी चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिसकी वजह से पूर्ण पैमाने वाले निर्णायक पारंपरिक युद्ध की संभावना खत्म हो गई है। भविष्य के युद्ध सीमित समय और स्थान में लड़े जाएंगे; उनमें सटीक मार करने वाले घातक सैन्य टेक्नोलॉजी और तेज कार्रवाई का बोलबाला रहेगा। इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर सटीक उदाहरण है। ऐसी लड़ाई में, विवादित सीमा पर जमीन पर कब्जा करने के लिए अग्रिम ऑपरेशन किए जाने की ज्यादा संभावना रहेगी। ऐसे खतरे पैदा करने या उनका मुक़ाबला करने के लिए बहुत तेज कार्रवाई करने वाले समूहों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चुनौती उसे लागू करने की है।

पारंपरिक ब्रिगेडों को तो ऑपरेशन से पहले डिवीजनों के संसाधनों से मजबूत बनाकर कंबाइंड आर्म्स ग्रुप्स में तब्दील किया जाता था, लेकिन IBG का गठन 5,000-6,000 सैनिकों वाले आत्मनिर्भर कंबाइंड आर्म्स समूह के रूप में किया जाता है। इसका गठन युद्धक्षेत्र के स्वरूप, मिशन, और दुश्मन की ओर से संभावित खतरों के मद्देनजर किया जाता है। यह मेकेनाइज्ड फोर्स हो सकता है या मुख्यतः पैदल सेना वाला या दोनों के मेल वाला हो सकता है। एक अकेले कमांडर के अधीन इसकी अपनी तोपें, अपने यूएवी, इंजीनियर, एअर डिफेंस, खुफिया तंत्र, इलेक्ट्रोनिक साज-ओ-सामान, संचार व्यवस्था, और सैन्य साजोसामान होंगे। तेजी और लचीलापन बनाए रखने के लिए कोर के संसाधनों से युद्ध लड़ने के साधन और साजोसामान से मदद जारी रहेगी। यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि 17 कोर के अंदर पांच IBG और एक स्नस्त्र का गठन एक पाइलट प्रोजेक्ट है, जिसे दो साल में पूरा किया जाना है। इसलिए संगठन और संयोजन में और बदलाव हो सकता है। लेकिन हरेक IBG में कुछ समान विशेषताएं होंगी।

पहली विशेषता यह होगी कि सच्चा कंबाइंड-आर्म्स एकीकरण होगा जिसमें लड़ाई लड़ने, लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने, और साजोसामान से समर्थन के तत्व शामिल होंगे। आर्मर, इन्फैन्ट्री, और मेकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री का एकीकरण जरूरत के मुताबिक होगा या संयुक्त यूनिटों के रूप में होगा।

दूसरी विशेषता यह होगी कि हरेक IBG के साथ एक अभिन्न खुफिया तंत्र, निगरानी और टोही (ISR) यूनिट जुड़ी होगी, जिसमें सिर्फ उसके लिए टोही, यूएवी, इलेक्ट्रोनिक युद्ध और सिग्नल इंटेलिजेंस सब-यूनिटें होंगी।

तीसरी विशेषताः हर एक IBG का अपना तोपखाना होगा, और दूर तक सटीक मार करने वाली क्षमता होगी जो पारंपरिक तोपों की रेंज से आगे तक मार कर सकेगी, और यह सब उसका अपना होगा या एफएसजी से हासिल होगा। फायर करने की व्यवस्था तत्काल सक्रिय होने वाले सेंसर नेटवर्क से जुड़ी होगी। भावी युद्धक्षेत्र इस बात से परिभाषित होगा कि जो नजर में आ रहा है उसे पहचाना जाए और मिनटों में खत्म किया जाए।

चौथी विशेषताः कमांड और कंट्रोल सिस्टम एआई-सक्षम युद्धक्षेत्र प्रबंधन और ऐसे निर्णय व्यवस्था का इस्तेमाल करे जो उपग्रहों, ड्रोनों, रडारों, और जमीनी सेंसरों से हासिल डाटा को मिलाकर ऑपरेशन की एक साझा तस्वीर तैयार करे।

पांचवीं विशेषताः साजोसामान को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया जाए जिसके साथ भविष्य के लिए रखरखाव, स्वायत्त आपूर्ति, गोला-बारूद के अलग-अलग भंडार, और डिजिटल इनवेंटरी के प्रबंधन की व्यवस्था शामिल हो।

उपरोक्त क्षमताओं के बिना गठित IBG छोटे डिवीजन से थोड़े ही बेहतर होंगे। भारत ब्रिगेड-केंद्रित मॉडल को अमेरिकी सेना द्वारा इसे अपनाए जाने के करीब दो दशक बाद और चीनी सेना पीएलए के एक दशक बाद लागू कर रहा है। इसलिए चुनौती उनके ढांचे की नकल करने की नहीं बल्कि सीधे छलांग लगाकर ड्रोन-समर्थित नेटवर्क से जुड़ी युद्ध प्रणाली को अपनाने की है। चीन ने सेना में जो सुधार किए हैं, वे शायद ज्यादा प्रासंगिक हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता सुधारों की सुस्त गति को लेकर है। XVII कोर के दो डिवीजन को अगर पांच IBG और एक एफएसजी में बदलने में दो साल लगते हैं, तो इस मॉडल को बाकी सेना पर लागू करने में दस साल और लगेंगे। भारत के लिए जो रणनीतिक माहौल है उसमें यह समयसीमा कारगर नहीं होगी।

(द प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

आशुतोष भैया के लिए प्राण झोंक दिए जाएंगे

'एक-एक दरवाजे पर जाऊंगा...', भाषण देते समय रोने लगे नरोत्तम मिश्रा; फिर सीएम ने संभाला

दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भरा नामांकन

भोपाल (नप्र)। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। हालांकि, नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में एक ऐसा भावुक पल आया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

दतिया के किला चौक पर आयोजित भाजपा की सभा में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा में फूट की बातें कर रही है, लेकिन पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरी है और कार्यकर्ताओं के दम पर जीत दर्ज करेगी।

अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की राजनीति में स्पष्ट अंतर है।

16 जुलाई से यही जमाऊंगा डेरा- नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं 16 जुलाई से यहीं पर डेरा जमाऊंगा। मैं क्षेत्र में एक-एक दरवाजे पर जाकर अपना शीश नवाऊंगा। मैं एक-एक गांव के अंदर जाऊंगा। यह कहते हुए नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पास खड़े आशुतोष तिवारी के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।

भावुक होकर कहा कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा- आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद देते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर दतिया की जनता का अभिवादन किया औ मंच की ओर चले गए।

कांग्रेस पर किया हमला- सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र की बात है तो अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए। पूरे देश में एक सामान कानून की बात होनी चाहिए। कांग्रेसी इससे मुंह छुपा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की पार्टी है, यह राजा-महराजाओं की पार्टी नहीं है।

दतिया उपचुनाव- भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी

दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रस्तावित स्टार प्राचरकों की सूची सामने आई है। 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई सूची सोमवार सुबह सामने आई है। इस सूची में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर संगठन के बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। इस सूची में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है।सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा खुद प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं।

सुप्रभात

इस सफ़र में हमसफ़र भी था ; अब याद क्या करना उसे
यानी शहर में एक घर भी था ; अब याद क्या करना उसे

वो हबीब था, वो करीब था, वो धड़कनों–सा अज़ीज़ था
वो ज़रा–सा बेख़बर भी था ; अब याद क्या करना उसे

हँसता न था, रोता न था, उसे इल्म न था दर्द का
वो ज़िंदा इस क़दर भी था ; अब याद क्या करना उसे

वो गली गली में फिरा किए, बस नाम तेरा लिया किए
कुई गाँव उसका बसर न था ; अब याद क्या करना उसे

वक़्त के सैलाब में, फिर ग़ुम हुआ यूं ख़्वाब में
वो खुशबू था, पैकर न था ; अब याद क्या करना उसे

कुछ अच्छे लोग रहते थे और कहने वाले कहते थे
इस दश्त में इक शहर था ; अब याद क्या करना उसे।

- मोहन सगोरिया

प्रदेश से कहां गया मानसून? एकदम से थम गई बारिश

- **15-17 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना**

भोपाल (नप्र)। एमपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, राज्य में मानसून को ऊर्जा देने वाली मौसम प्रणालियां कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम सा गया है। हालांकि, किसानों और आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिससे जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश भर में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की जोरदार संभावना है।

पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी या अति भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। अगले दो से तीन दिन प्रदेश में बारिश को लेकर कोई बड़ा अपडेट या अलर्ट भी नहीं है। हालांकि 15 जून से मौसमी परिस्थितियां बदलेंगी और एक बार फिर जोरदार बारिश का सिस्टम बनने की संभावना है।

क्यों कमजोर पड़ा मानसून?

मौसम विशेषज्ञ डॉ. शैलेंद्र नायक के अनुसार मानसून को सक्रिय बनाए रखने वाली प्रमुख मौसमी प्रणालियां फिलहाल कमजोर हो गई हैं या उनका प्रभाव मध्य प्रदेश से दूर चला गया है। इसी वजह से प्रदेश में व्यापक बारिश नहीं हो रही और अधिकांश क्षेत्रों में केवल बादल व हल्की फुहार जैसी स्थिति बनी हुई है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया चक्रवात- मौसम विभाग के विस्तारित अवधि पूर्वानुमान के अनुसार, 13 से 19 जुलाई के बीच उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बनने जा रहा है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो यह मजबूत होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। यह सिस्टम ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रास्ते पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगा।

पूर्वी एमपी में हल्की फुहारें

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां केवल पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी रहीं। मऊगंज के हनुमना में 16 मिमी, नैगढ़ी में 4 मिमी, सीधी के सिहावल में 3 मिमी, गोपदबनास में 1.2 मिमी और अनूपपुर के बिजुरी में 1.1 मिमी पानी गिरा। वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहा और कहीं भी उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं की गई। गरज-चमक की स्थिति कमजोर रहने के कारण भिंड में हवा की अधिकतम रफ्तार 35 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।

काशी, मथुरा और संभल पर नहीं बन पाई बात

- **हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने ठुकराया सुप्रीम मध्यस्थता का प्रस्ताव**
- **दोनों पक्ष सहमत नहीं, कहा-केस लड़कर फैसला चाहते हैं**

वाराणसी/मथुरा/संभल (एजेंसी)। यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समाधान समारोह 2026 पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने यह लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लड़कर फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद

विवाद क्या है:वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां मौजूद प्राचीन विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी।

मुस्लिम पक्ष की मांगः ज्ञानवापी को मस्जिद के रूप में बरकरार रखा जाए। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत नए दावों को खारिज किया जाए। मस्जिद में मुस्लिमों के नमाज के अधिकार सुरक्षित रहें।

मथुरा विवाद

विवाद क्या हैः मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांगः शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए। मुस्लिम पक्ष की मांगः मस्जिद को वैध धार्मिक स्थल माना जाए।

शाही जामा मस्जिद विवाद (संभल):विवाद क्या हैः संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन हरिहर (हरि) मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष की मांगः मस्जिद का पुरातात्विक सर्वे कराया जाए। मंदिर के अवशेष मिलने पर बहाल किया जाए।

खामेनेई की मौत से गुस्साए ईरान की 'हिट लिस्ट' में ट्रंप

नेतन्याहू और स्टार्मर सहित 13 नेताओं के और नाम हैं शामिल

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान की जंग के बीच एक और घटनाक्रम इस समय चर्चा का विषय बन गया है। ईरान के एक अखबार ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए टारगेट किए जाने वाले लोगों की एक लिस्ट छापी है। इस लिस्ट में अमेरिका, इजरायल और यूरोपियन देशों के नेता शामिल हैं। इस अखबार में एक पोस्टर छापा गया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य बड़े नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह लिस्ट ईरान की राजधानी में अधिकारियों द्वारा पब्लिश किए जाने वाले हमशहरी अखबार में छापी गई है। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन दी- अचानक मौत के लिए तैयार रहें। साथ ही मोजतबा खामेनेई का बयान भी छापा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए।

शताब्दी में एक्सपायरी ब्रेड परोसने पर आईआरसीटीसी का बड़ा एक्शन

वेंडर पर 1 लाख जुर्माना, लापरवाही बरतने पर मैनेजर समेत स्टाफ को हटाया

भोपाल (नप्र)। नई दिल्ली से रानी कमलापति (भोपाल) आ रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड परोसे जाने के मामले में आईआरसीटीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। कैटरिंग वेंडर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि मामले में लापरवाही सामने आने पर मैनेजर सहित संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया है।

वेंडर पर 1 लाख की पेनल्टी

मीडिया को विवेक रावत ने बताया कि एक्सपायरी ब्रेड परोसने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित कैटरिंग वेंडर पर एक लाख रुपए की आर्थिक पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही, जिस स्टाफ की जिम्मेदारी थी, उसे तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भोपाल ■ मंगलवार, 14 जुलाई 2026

बहुरेंगे भीगने वाले दिन जमकर बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान, गुजरात और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों में कमजोर

● 7 दिन में कई राज्यों में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून ● अभी राजस्थान-गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर ● यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट

पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है।

- **उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 126 सड़कें बंद-** उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। स्यानाचट्टी के पास ऋषिकेश-यमुनोत्री हाईवे रविवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। हरियाणा में हिमाचल से आ रहे पानी के कारण यमुना और मारकंडा नदी में पानी बढ़ गया है। इससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में बह गए।
- **राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून-** राजस्थान में मानसून का पहला दौर थमने के बाद अब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले करीब एक हफ्ते तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि, 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5-6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो

सुप्रीम फैसला, असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और

उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का सवाल संविधान और कानून से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सभी मामले दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिए गए है। इन लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

ई 20 पेट्रोल से खराब हो रही गाड़ियों पर सरकार सख्त

राज्यों को दिया मिलावटखोरों पर कड़ा ऐक्शन लेने का निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। ई 20 पेट्रोल इस समय देश में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बना हुआ है। सरकार इसको देशभर में लागू कर चुकी है। हालांकि, लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों में खराबी आ रही है, इंजन खराब हो रहा है और माइलेज कम हो रहा है। लोगों में ई 20 पेट्रोल की क्वालिटी और इंजन सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं देखी जा रही हैं। इस सबके बीच मोदी सरकार काफी सख्त है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पेट्रोल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। **मिलावटखोरों से कड़ाई से निपटने का आदेश-** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक नोट जारी किया था। मंत्रालय ने निर्देश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ईंधन के रखरखाव या सप्लाई चेन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

डीएमके को दुश्मन कहने वाले विजय से दोस्ती संभव नहीं

चेन्नई (एजेंसी)। थलपति विजय की पार्टी टीवीके अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो डीएमके विपक्षी दलों के गुट से बाहर हो जाएगा। डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने बीजेपी विरोध के नाम पर सीएम विजय से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। डीएमके सांसद गणपति पी. राजकुमार ने कांग्रेस

पर भी पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि सीएम विजय बार-बार डीएमके को अपना दुश्मन बता चुके हैं, ऐसे में हम उनके साथ इंडिया गठबंधन में साथ कैसे हो सकते हैं। पार्टी ने साफ किया कि बीजेपी के विरोध के नाम पर तमिलनाडु में केरल और पश्चिम बंगाल वाला मॉडल नहीं चलेगा। यहां तो डीएमके वाला ही मॉडल चलेगा।

हाय महंगाई, तू कहां से आई

● 17 महीनों में पहली बार आरबीआई के टारगेट से ऊपर ● जून में महंगाई ने पकड़ी रफ्तार, बढ़कर 4.38 फीसदी हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। जून में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 फीसदी हो गई। इसकी वजह खाने-पीने की चीजों और ईंधन की ऊंची कीमतें, पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और मॉनसून के असमान रहने की चिंताएं थीं। इनसे कीमतों पर दबाव बना रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ताजा आंकड़ा 17 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 फीसदी के मीडियम-टर्म इनफ्लेशन टारगेट से ऊपर चला गया। इससे कम महंगाई का लंबा दौर खत्म हो गया। सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों से पता चला कि रिटेल इनफ्लेशन रेट मई के 3.93 से बढ़कर जून में 4.38 फीसदी हो गई। यह मोटे तौर पर बाजार की उम्मीदों के मुताबिक थी।

- **अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी-** अर्थशास्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी कि ग्लोबल एनर्जी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। रुपये के कमजोर होने की संभावना है। इंपोर्टेड महंगाई बढ़ सकती है। जबकि अनियमित मॉनसून के कारण साल के बाकी समय में खाने-पीने की चीजों की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।

अनुमान से ज्यादा है आंकड़ा

रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के एक पोल में इस महीने के लिए कंज्यूमर महंगाई दर 4.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। इसमें अनुमान 3.65 से 5.50 फीसदी के बीच थे। जून का यह आंकड़ा तब से सबसे ज्यादा है जब भारत ने इस साल की शुरुआत में नए बेस ईयर और अपडेटेड कंजम्पशन बास्केट के साथ अपनी संशोधित सीरीज अपनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की पांच साल की अवधि के लिए हेडलाइन रिटेल इनफ्लेशन रेट को 4 फीसदी पर बनाए रखने का काम सौंपा गया है। साथ ही इसे 2 से 6 फीसदी की टॉलरेंस रेंज के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। जून में रिटेल फूड इनफ्लेशन रेट 5.32 रही, जबकि मई में यह 4.78 थी। ग्रामीण इलाकों में भी संकट है।

मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव

महंगाई दर का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जून की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने और अपने न्यूट्रल पॉलिसी रुख को बनाए रखने के कुछ हफ्तों बाद आया है। कारण है कि नीति-निर्माताओं ने महंगाई के जोखिमों और आर्थिक विकास को सहारा देने की जरूरत के बीच संतुलन बनाया था। सेंट्रल बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने महंगाई दर के अनुमान को भी अप्रैल में लगाए गए 4.6 से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया था। इसका कारण चीजों की कीमतों का लगातार बढ़ना है।

देश के लिए 3 जंग लड़ने वाले पूर्व सैनिक से धोखाधड़ी!

90 साल की उम्र में चुन्नीलाल अपनी ही जमीन के लिए कर रहे संघर्ष

जैसलमेर (एजेंसी)। जिस योद्धा ने 1962 में चीन और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वह आज अपनी ही जमीन को बचाने के लिए 90 साल की उम्र में लाठी टेकते हुए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 1962, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों के गवाह रहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी कैप्टन चुन्नीलाल के साथ जैसलमेर में

जो हुआ, उसने सीमावर्ती इलाके में चल रहे एक बहुत बड़े और संगठित लैंड स्कैम की पोल खोल दी है। कैप्टन चुन्नीलाल को पोंग बांध विस्थापित होने के नाते मोहनगढ़ क्षेत्र में सरकार ने एक कृषि भूमि आवंटित की थी। हिमाचल में रहने के कारण वे यहां बटाई पर खेती करवाते थे। भू-माफिया ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। 16 जून को उपनिवेशन तहसील में एक डमी चुन्नीलाल खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई और महज 6 दिन के भीतर, यानी 22 जून को उसका म्यूटेशन भी हो गया। आम आदमी जिस म्यूटेशन के लिए महीनों चक्कर काटता है, वह जालसाजों के लिए हफ्तेभर में कैसे हो गया। यह सवाल अब उपनिवेशन विभाग के अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहा है।

- **एसपी के दखल के बाद जागा सिस्टम-** हैरानी की बात यह है कि देश के इस जांबाज के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर को फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों की खाक छाननी पड़ी। जब मामला जैसलमेर एसपी के पास पहुंचा, तब जाकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है कि आखिर कंप्यूटरों में बंद सरकारी डेटा इन भू-माफियाओं तक कैसे लीक हो रहा है। देश की रक्षा करने वाले एक वयोवृद्ध सैनिक के साथ हुआ यह कृत्य अब स्थानीय जनता और पूर्व सैनिकों के बीच भारी आक्रोश का कारण बन चुका है।

मैं बिहार आकर अपना सुदर्शन चक्र चलाऊंगा

● वीणा मानवी को हिरासत में लेने पर भड़के तेज प्रताप

पटना (एजेंसी)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में हर दिन एक नया और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिल रहा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच, तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन प्रक्रिया पूरी करते ही पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर से हिरासत में ले लिया। इस हाई-प्रोफाइल ऐक्शन के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। फिलहाल दिल्ली में मौजूद पार्टी संरक्षक तेज प्रताप यादव ने इस पूरी कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प्रत्याशी को जानबूझकर एक झूठे मामले में फंसाकर चुनाव प्रक्रिया से दूर करने की साजिश रची जा रही है। **नॉमिनेशन करते ही वीणा को पुलिस ने दबोचा-** अब तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी वीणा मानवी को नामांकन के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया है।

महाकाल-हरसिद्धि मार्ग का नामकरण पं. सूर्यनारायण व्यास के नाम पर होगा

उज्जैन। ज्योतिर्विद्या के प्रख्यात पंडित पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जिन्होंने आजादी के बाद उज्जैन को विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर जैसी सौगातें दी और अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आरम्भ वर्ष 1928 से किया और बाद में सिंधिया शोध प्रतिष्ठान, कालिदास अकादमी जैसी सांस्कृतिक संस्थायें स्थापित की अब प्रशासन महाकाल से हरसिद्धि मार्ग का नामकरण पंडित सूर्यनारायण व्यास के नाम से करने जा रहा उल्लेखनीय है कि आगामी सिंहस्थ को देखते हुए शहर में विकास और चौडीकरण के बड़े कार्य चल रहे हैं,इसी सिलसिले में श्रीमहाकालेश्वर मन्दिर के समीप स्थित भारती भवन के सामने की कुछ जमीन , पंडित पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास के सुपुत्र राजशेखर व्यास ने प्रशासन को निशुल्क प्रदान करने की सहमति दी है। अखिल भारतीय कालिदास परिषद के अध्यक्ष श्री राजशेखर व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रदेश सरकार की शहर के विकास की योजनाओं में सभी सहयोग कर रहे हैं और भारती भवन के हिस्से की जमीन, सड़क चौडीकरण के लिए नि:शुल्क प्रदान कर हम भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। पंडित जी भी शहर के विकास के लिए कृतसंकल्पित रहे और महाकाल के इस महान भक्त ने महाकाल में शंख द्वार, चाँदी द्वार, मोजेक टाइल्स भी लगवायी,क्षिप्रा द्वार बनाया,बोहरा वार्ड बच्चों का अस्पताल बनवाया और आधुनिक उज्जयिनी का जो रूप हैं वह पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास की देन है।

कुख्यात वन्यजीव शिकारी अजीत पारधी की जमानत निरस्त

● मध्यप्रदेश लाया जाएगा आरोपी, चंद्रपुर महाराष्ट्र में न्यायिक हिरासत में है निरुद्ध

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पेंच टाइगर रिजर्व में वर्ष 2013 में दर्ज वन्यजीव शिकार प्रकरण के कुख्यात आरोपी अजीत पारधी की जमानत विशेष न्यायालय, जबलपुर ने निरस्त कर दी है। न्यायालय अब आरोपी की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा, जिसके बाद उसे महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाया जाएगा। वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में यह प्रदेश का एक विरला मामला है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 480 के तहत जांच एजेंसी के आवेदन पर पहले से जमानत प्राप्त आरोपी की जमानत और बंधपत्र निरस्त किए गए हैं। विशेष न्यायालय, जबलपुर से सशर्त जमानत मिलने के बाद भी एसटीएसएफ उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए थी।

गो हत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कहा-इसमें सुधार की जरूरत, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था-ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय हैं, तब अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया था

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़ों और दुधारू-पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 की धारा-4 का उल्लेख किया। इसमें कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को ही प्रमाणपत्र मिलने के बाद काटा जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए।

इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था- मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को (बकरीद से एक दिन पहले) तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा-संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है।

कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था-बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं- 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा, खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह बैन है। ईद-उल-जुहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पूर्व तृणमूल नेता व विधायक हुमायूं कबीर ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए ईद पर हर हाल में कुर्बानी की धमकी दी है।

पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता पर कार्यक्रम

भोपाल। सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की निदेशिका स्मिता कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी क्रमांक 1146, गोविंदपुरा में बाल, महिला एवं एलजीबीटीक्यू के मानसिक समस्या को समझने के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं पुनर्वास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पहचान के साथ की गई। आंगनवाड़ी से गर्भवती एवं प्रसूति महिलाएँ जुड़ी रहती है, इसलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस

कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दो महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर इससे जुड़ी अपनी व्यक्तिगत अनुभव साझा किया जो इससे गुजरी थी। इसके बाद बौद्धिक अक्षमता और ऑटिज्म वाले बच्चे की शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप से बेहतर पुनर्वास तक की आधारभूत जानकारी दी गई, ताकि लोग जागरूकता से ऐसे बच्चों की पहचान कर उचित समय पर बिना लापरवाही थेरेपी से जोड़ सकें। आंगनवाड़ी सहायिका निशा यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम से मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता सम्बंधित जानकारी मिल रही है, इससे उन्हें यह फायदा हुआ है कि अब वह इस तरह की महिलाएँ और बच्चों के लिए उनके आंगनवाड़ी से जुड़े लोगों को उचित जानकारी दे पाएंगी। प्रतिभागियों और आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि इससे पहले उनके केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य पर और लिंग आधारित भेदभाव पर कई सवाल-जवाब हुए, इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी की सहायिका और लगभग 28 महिलाएँ एवं बच्चे शामिल हुए।

कैदियों को कोर्ट तक लाने में अपनी जेब से खर्च करते हैं पुलिसवाले

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों द्वारा कैदियों को कोर्ट ले जाने के दौरान होने वाले खर्च को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर

मंगलवार तक यह बताने को कहा है कि क्या अदालतों में कैदियों को ले जाने वाले पुलिसकर्मियों को उनके रहने और खाने पर खर्च होने वाले पैसे का रीइंबर्समेंट मिलता है या नहीं। यह मामला रीवा के दहेज उत्पीड़न और हत्या के दोषी अब्दुल माजिद की अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आया। माजिद को रीवा से 250 किलोमीटर दूर जबलपुर हाईकोर्ट लाया गया था।

सुनवाई के दौरान जजों के सामने खुली पोल

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए. के. सिंह की बेंच ने कैदी माजिद को लेकर आए एएसआई हरीलाल वर्मा और हेड कांस्टेबल महेश वर्मा से पूछा कि क्या कैदी ने खाना खाया और क्या उन्हें कैदियों को खाना खिलाने के लिए कोई अलग से फंड या आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च मिलता है?
पुलिसकर्मियों के जवाब ने जजों को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि कैदियों के ठहरने और खाने-पीने पर खर्च होने वाले पैसे की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें यह पूरा खर्च अपने खुद के दैनिक भत्ते से उठाना पड़ता है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।

धनंजय वर्मा स्मृति आलोचना सम्मान प्रो. अरविंदाक्षन का समारोह आज

भोपाल। आचार्य धनञ्जय वर्मा सृजन पीठ, भोपाल द्वारा भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना के समन्वयक, रचना के सहयात्री आलोचक धनञ्जय वर्मा की स्मृति में वर्ष 2026 के सम्मान से केरल के हिन्दी और मलयाली भाषा के वरिष्ठ कवि, आलोचक प्रो. ए. अरविंदाक्षन को सम्मानित किया जाएगा।
सम्मान समारोह 14 जुलाई को शाम 5 बजे मायाराम सुरजन भवन, शास्त्री नगर भोपाल में आयोजित होगा। सम्मान स्वरूप रु. 21 हज़ार की राशि, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र के साथ उन्हें भेंट की जाएगी। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक निवेदिता वर्मा ने दी।

टेक हब बन रहा है एमपी, स्पेन की कंपनी स्थापित कर रही डेटा सेंटर

40,000 करोड़ रुपए का आएगा निवेश : सीएम

भोपाल (नप्र)। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया है। इस कॉन्क्लेव का मकसद डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि एमपी टेक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने 20 औद्योगिक इकाइयों का भी लोकार्पण किया है। समारोह में इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया गया।

- **टेक में भी आगे बढ़ा रहा है एमपी-** सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान भी पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट थी, लेकिन अब डिफेंस से लेकर ड्रोन, साइंस टेक से लेकर रिन्युएबल एनर्जी, इंडस्ट्री कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर गोइंग सेक्टर तक एमपी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्रोथ कॉन्क्लेव तीसरे संस्करण तक पहुंच गया है। पिछले दो वर्षों में हमने जो संकल्प लिए, उन्हें पूरा किया। दो संस्करणों में हमें 46 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, 22 नए औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण हुआ और 4 नई परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया गया।
- **12 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश धरातल पर उतरे-** उन्होंने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12 हजार करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इससे हमारी काम करने की गति और आत्मविश्वास झलकता है। मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भी भोपाल पहचाना जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी दुनिया के सामने राष्ट्र भाषा को गौरवांवित करते हैं।
- **स्पेन की कंपनी स्थापित कर रही डेटा सेंटर-** मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से अब तक 28 हजार 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। बार्सिलोना (स्पेन) के सबमर ग्रुप ने अपने संकल्प को दोहराया है और 1 गीगा बाइट के डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार एआई, डाटा सेंटर और सेमीकंडकर सहित सभी छोटे और बड़े उद्योगों के विकास के लिए सदैव तत्पर है। मध्यप्रदेश डीप टेक पार्क और डाटा सेंटर सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। एआई से लेकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

सीएम ने की तीन बड़ी घोषणाएं

- इंदौर आईटी कॉरीडोर में 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के अत्याधुनिक आईटी पार्क का विकास किया जाएगा
- सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- इस क्षेत्र में कौशल विकास एवं उद्योग क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करेगा
- भोपाल में 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र का बड़ा आईटी पार्क बनेगा

भारी निवेश करने जा रहीं कंपनियां

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि जीआईएस में प्रदेश को अभूतपूर्व निवेश मिला। इसमें 10 लाख करोड़ निवेश धरातल पर उतर चुका है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इसी औद्योगिक निवेश यात्रा का एक पड़ाव है। मध्यप्रदेश में जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निवेश और भविष्य की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक 12 हजार करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर आ चुका है और आगे भी इस पर काम हो रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में अलग-अलग दिग्गज टेक कंपनियां 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही हैं।

लोडिंग वाहन से भिड़ी बाइक, सड़क पर बिखरे सामान में बारहसिंगा के सींग निकले

पट्टी कराकर थाने ले गई पुलिस

मंडला (नप्र)। जिले में एक अजीबोगरीब सड़क हादसे ने वन्यजीव शिकारी की पोल खोलकर रख दी। देवदरा गांव के राजीव कॉलोनी के पास एक मालवाहक गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद बाइक सवार का सामान सड़क पर बिखर गया, जिसे देखकर वहां मौजूद राहगीर दंग रह गए। बिखरे हुए सामान के बीच प्रतिबंधित बारहसिंगा के सींग छिपे हुए थे। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक सवार 29 वर्षीय सुशील सिंधिया को हिरासत में ले लिया। जब उससे सींगों को लेकर पूछताछ की गई, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

वन विभाग ने शुरू की जांच- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बारहसिंगा के सींगों को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी सुशील सिंधिया के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वन विभाग की टीम आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

जिला अस्पतालों के उन्नयन एवं पद स्वीकृति की कार्यवाही प्राथमिकता से करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

विशेषज्ञों की भी पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाते हुए सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जिला अस्पतालों के उन्नयन तथा नवीन पदों के सृजन एवं स्वीकृति से संबंधित विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभाव एवं बेहतर हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नर्सिंग भर्ती परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन किया जाए तथा पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि

बांडधारी चिकित्सकों के पोस्टिंग आदेश शीघ्र जारी कर चिन्हित चिकित्सकों की समय पर पदस्थापना एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्सकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, श्री अशोक बर्णवाल उपस्थित थे।

पहली ही बारिश में बह गया सिंगरौली का नया चेक डैम

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, सचिव सस्पेंड, सब-इंजीनियर की छुट्टी तय

सिंगरौली (नप्र)। जिले से भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के देवसर जनपद पंचायत के अंतर्गत कठदहा गांव में घघिया नाले पर बना एक नया चेक डैम सीजन की पहली ही बारिश में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हैरानी की बात यह है कि इस चेक डैम का निर्माण महज दो हफ्ते पहले ही पूरा हुआ था।

बांध के टूटते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने तुरंत इस मामले में तकनीकी जांच के आदेश दिए, जिसमें निर्माण कार्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

बिना लोहे के खड़ा कर दिया ग्रेविटी डैम- तकनीकी जांच रिपोर्ट में सामने आया कि चेक डैम के निर्माण में तय नियमों और पैमानों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। नियमों के मुताबिक बांध की नींव कम से कम 1 मीटर गहरी होनी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदारों ने इसे बेहद उथला रखा। सबसे गंभीर बात यह रही कि ग्रेविटी डैम के डिजाइन में किसी भी तरह के लोहे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जिससे पहली ही बारिश के पानी का

दबाव बांध झेल नहीं सका। इसके अलावा, सब-इंजीनियर ने बिना किसी फाइनल मेजरमेंट और मूल्यांकन के ही काम को पास कर दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही प्रोजेक्ट के पैसे भी निकाल लिए।

कलेक्टर का बड़ा एक्शन- खामियां उजागर-नींव 1 मीटर से कम खोदी गई, लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ और डाउनस्ट्रीम स्लोप भी मानकों के विपरीत था।

पैसे की निकासी- बिना काम के मूल्यांकन के ही ग्राम पंचायत ने 15वें वित्त आयोग के फंड से करीब 4 लाख रुपये निकाल लिए।

सचिव सस्पेंड- जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने लापरवाही के आरोप में ग्राम सचिव बिहारी लाल साकेत को निलंबित कर दिया है।

सरपंच पर गाज- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत कठदहा गांव के सरपंच दिलशरण सिंह को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

इंजीनियर को नोटिस- सब-इंजीनियर सतीश पटेल को सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह चेक डैम 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत द्वारा बनाया गया था और इसे अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। पंचायत द्वारा अब तक करीब 4 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। हमने सचिव को सस्पेंड कर दिया है, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया चालू है और सब-इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया है।

इसके साथ ही सरकारी धन की रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने सभी आरोपियों को अपनी सफाई पेश करने के लिए आखिरी समय सीमा दी थी, जिसके बाद अब एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल में रिवॉल्वर छीनकर किसान को मारी गोली

पैर को चीरते निकली बुलेट; थार हटाने के लिए हॉर्न बजाने पर भड़के 3 युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मिसरोद इलाके में किसान को गोली मारने का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में तीन युवक पहले किसान से मारपीट करते हैं, फिर उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर दो फायर कर देते हैं। एक गोली किसान के पैर को चीरते हुए निकल जाती है, जबकि दूसरी मिस हो जाती है। घटना शनिवार देर रात सागर रॉयल होम्स की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

किसान को गोली और रायसेन में तालिबानी प्रताड़ना, उमंग सिंघार ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा- मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। प्रदेश

की राजधानी भोपाल में एक किसान को सरेआम गोली मारे जाने और रायसेन जिले में चोरी के महज शक में दो युवकों को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने व करंट लगाए जाने का मामला सामने आया है। इन दोनों ही गंभीर घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य की मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला है। उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का नहीं, बल्कि तालिबानी शासन चल रहा है।

भीड़ के मन से खत्म हो चुका है कानून का डर- नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भोपाल और रायसेन में हुई ये दोनों ही घटनाएं साफ बताती हैं कि प्रदेश में अपराधियों के साथ-साथ अब आम भीड़ के मन से भी कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। जब सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था को संभालने में विफल हो जाते हैं, तब अपराधी बेखौफ घूमने लगते हैं और आम लोग भी न्याय को अपने हाथ में लेने लगते हैं। सिंघार ने इसे किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बेहद खतरनाक स्थिति बताया।

मुख्यमंत्री से सीधे पूछे सवाल- उमंग सिंघार ने सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए जनता की तरफ से जवाब मांगा है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर प्रदेश का आम नागरिक और किसान कब सुरक्षित महसूस करेगा?

पुलिस विभाग में सूबेदार और कार्यवाहक आरआई के प्रमोशन

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग में प्रदेश के 168 सूबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।

जीएडी के पत्र के बाद शुरू हुई प्रमोशन प्रक्रिया- बता दें कि 30 जून 2026 को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र और मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के विधिक परामर्श के अंतर्गत यह प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आदेश के तहत प्रमोट हुए अधिकारियों को रक्षित निरीक्षक के रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। इन सभी अधिकारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत पे-मेट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 9300-34800 + 4200) का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा। विभागीय जांच या अधूरी ट्रेनिंग वाले अफसर नहीं होंगे रिलीव

संपादकीय

त्रिपक्षीय समझौता : नुकसान में नफा !

सरदार सरोवर परियोजना मामले में केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से हुए त्रिपक्षीय समझौते को लेकर मध्यप्रदेश सरकार जो स्पष्टीकरण दे रही है, जो किसी के गले नहीं उतर रही है। जो बातें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राज्य सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार के दबाव में ऐसे समझौते पर हामी भर दी है, जिसमें उसका ही नुकसान है, जबकि सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को हुआ है। हालांकि मप्र की मोहन यादव सरकार अभी भी यही दावा कर रही है कि हमारा नुकसान में भी नफा ही है। प्रदेश में नर्मदा आंदोलन की पुरोधा रही मेधा पाटकर ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि वह सच्चाई क्या है, यह जनता को बताए। क्या मप्र ने अपना दावा छोड़ दिया है? सुश्री पाटकर ने पूरे समझौते पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र की 7669 करोड़ रुपये की वैध भरपाई और पुनर्वास के लिए 2900 करोड़ रुपये के दावे की अनदेखी हुई है। विवाद में मध्य प्रदेश में जलमग्न हुई वन भूमि, शासकीय भूमि और अन्य सार्वजनिक संसाधनों की भरपाई का मुद्दा शामिल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगातार गुजरात से कानूनी रूप से अपेक्षित वित्तीय सहायता की मांग करते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री और जल संसाधन मंत्री की मध्यस्थता से हुए समझौते को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

मेधा पाटकर ने कहा कि समझौते का अधिकृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन प्रचारित खबरों में विरोधाभास हैं। उन्होंने परिप्रेक्ष्य को जानने और स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि किसी भी समझौते में मप्र सरकार और विस्थापितों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक सीमित थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना से होने वाली क्षति के लिए 281.46 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस राशि में वन क्षेत्र के लिए 112.51 करोड़ रुपये, सरकारी भूमि के लिए 157.61 करोड़ रुपये और जलमग्न वन भूमि के लिए 11.34 करोड़ रुपये शामिल थे। इसके बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 110 मीटर और फिर 121.92 मीटर की गई। वर्ष 2014 से बांध की ऊंचाई में और वृद्धि की गई और 2017 में इसे 138.68 मीटर कर दिया गया। बांध की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में डूब क्षेत्र का विस्तार होता गया, जिससे बड़ी मात्रा में वन भूमि, सरकारी भूमि, कृषि क्षेत्र और अन्य प्राकृतिक संसाधन जलमग्न हुए। इससे राज्य को होने वाली क्षति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई। विस्थापित गांवों की संख्या 2019 से 192 और एक नगर साबित हुई। 2023 में पुनरीक्षित बैकवॉटर स्तरों के आधार पर हजारों परिवारों को 'पुनर्वास के लिए अपात्र' घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ गई। इसी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जलमग्न भूमि और अन्य प्रभावित परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराया। 2019-2020 के आधार पर तैयार इस पुनर्मूल्यांकन के अनुसार, राज्य ने अपने डूब क्षेत्र की भरपाई के दावे को बढ़ाकर 7,669 करोड़ रुपये कर दिया। यह दावा बढ़े हुए डूब क्षेत्र और वर्तमान मूल्य के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था। 30 साल से अटके इस मामले पर 7 जुलाई को दिल्ली में समाधान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश को मुआवजा मिलना तो दूर, उल्टा गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह तो न्याय मिलने की जगह अन्याय होने जैसी स्थिति है, लेकिन मप्र सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाने की जगह जो हुआ, उसे ही फायदेमंद बता रही है। इससे संदेह और गहरा गया है।

नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

नाउम्मीद होने से काम नहीं चलने वाला

भारत को सभ्य बनाने आए अंग्रेज तो असभ्य थे ही क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में लूटपाट और दमन की ऐसी सभ्यता का विकास किया जिससे मुक्त होने में न जाने कितने वर्ष लगेंगे। लेकिन रामराज्य कायम करने और सनातन धर्म की स्थापना का एक नास्टैलजिया(अतीत मोह) पेश करके संघ परिवार इस सभ्यता के साथ जो कर रहा है वह तो और भी भयानक है। संघ परिवार का आख्यान इन मान्यताओं पर आधारित था कि भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक समाज हिंसक, क्रूर और असभ्य है। उसकी देशभक्ति भी संदिग्ध है। जबकि हिंदू समाज उदार, सभ्य और देशभक्त है। इसलिए हिंदू खतरे में है। इसी के साथ उसका यह मानना है कि समाजवाद, साम्यवाद, समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और संविधानवाद के विचार विदेश यानी यूरोप से आए हैं इसलिए वे भारत के लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। इन्हीं आख्यानों को आधार बनाकर संघ परिवार महत्व और अर्थ की संरचनाओं पर कब्जा करके एक नई सभ्यता का निर्माण करना चाहता है। हालांकि इस दौरान वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर नाजियों और फासीवादियों की प्रशंसा का जो भाव भरा है वह कहीं से भी स्वदेशी नहीं है। न ही आज अमेरिका और इजराइल के युद्धोन्मादी नेतृत्व की निकटता एक सभ्यता निर्माण में सहायक हो सकती है।

लेकिन संघ परिवार के सौ साल पूरे होने पर और केंद्रीय सत्ता में लगभग डेढ़ दशक तक बैठने के बाद और देश के अधिकतम राज्यों में सरकार चलाने और कुछ में तो दो दशक तक सत्ता पर कायम रहने के बाद देश का जो साभ्यतिक परिदृश्य बना है वह कहीं से भी सभ्यता की ओर नहीं जा रहा है। बल्कि भारत को असभ्य बनाने और वैश्विक स्तर पर कायम हो रही असभ्यता में सहायक बनने जा रहा है। मामला महज अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी (डकैती) का नहीं है, मामला उस पर कुतर्क करने और उसे मैनेज करने का है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत तो राम राम कहते हुए भागते दिखे लेकिन उनके दूसरे नंबर के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू विरोधी और राष्ट्रविरोधी लोग इसका इस्तेमाल हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं उसे रोकने के लिए धैर्य चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू समाज के इसी धैर्य ने उसे लंबे समय तक अन्याय के विरुद्ध बोलने और समता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज बनाने से रोके रखा। जो समाज अपने आंतरिक अन्याय से लड़कर उसे मिटाने का साहस न कर सके उसे निरंतर असभ्यता के गर्त में जाने से कौन रोक सकता है।

लेकिन असभ्यता का प्रदर्शन अयोध्या तक सीमित नहीं है। वह उस समय भी दिखता है जब दिल्ली से सटे लोनी इलाके में एक मुस्लिम युवक तालाब में नहाने के लिए निकलता है, उसकी बाइक से किसी कार वाले को खरोंच लग जाती है और उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार से होता है। नेताओं के कपड़े उतार कर और उनके गले में जूता डालकर घुमाया जाना कौन सी लोकतांत्रिक सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है। सांसदों को गिराकर मारना और

संघ परिवार का आख्यान इन मान्यताओं पर आधारित था कि भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक समाज हिंसक, क्रूर और असभ्य है। उसकी देशभक्ति भी संदिग्ध है। जबकि हिंदू समाज उदार, सभ्य और देशभक्त है। इसलिए हिंदू खतरे में है। इसी के साथ उसका यह मानना है कि समाजवाद, साम्यवाद, समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और संविधानवाद के विचार विदेश यानी यूरोप से आए हैं इसलिए वे भारत के लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। इन्हीं आख्यानों को आधार बनाकर संघ परिवार महत्व और अर्थ की संरचनाओं पर कब्जा करके एक नई सभ्यता का निर्माण करना चाहता है। हालांकि इस दौरान वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर नाजियों और फासीवादियों की प्रशंसा का जो भाव भरा है वह कहीं से भी स्वदेशी नहीं है। न ही आज अमेरिका और इजराइल के युद्धोन्मादी नेतृत्व की निकटता एक सभ्यता निर्माण में सहायक हो सकती है।

महिला सांसदों के ऊपर अंडे फेंकना, फिर सत्ता में बैठे लोगों का यह कहना कि अंडे को तो मेटल डिटेक्टर पकड़ नहीं सकता इसलिए नए किस्म की मशीन मंगाई जा रही है कोई हास्य है या असभ्य समाज की निशानी है। असभ्यता माब लिंचिंग के आरोपियों को सजा देने वाली मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम की जज तबस्सुम खान को धमकी देना भी है। असभ्यता मणिपुर में दो समुदायों को भिड़ाकर उससे दूर हट जाना है, जबकि कुछ साल पहले संघ के लोग यह दावा करते नहीं थकते थे कि उन्होंने पूर्वोत्तर के उग्रवाद और अलगाववाद को नियंत्रित करके वहां के समाज में शांति कायम किया और उन्हें मुख्यधारा में ला दिया है। असभ्यता फिलस्तीन में 20,000 बच्चों को इजराइली सेना द्वारा निशाना लगाकर मारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया न देना भी है। जबकि भारत के ही एक न्यायाधीश ने उस पर अपनी रिपोर्ट में इजराइली क्रूरता को उजागर किया है।

असभ्यता सांसदों और विधायकों की चोरी करना ही नहीं है असभ्यता वोटों की चोरी करना भी है। संघ परिवार के बारे में कर्नाटक के दलित लेखक देवनूर महादेव ने अपनी चर्चित पुस्तक 'आर.एस.एस-काया और माया' में लिखा है कि संघ के लोग 'मति फेरने और रूप बदलने' में माहिर होते हैं। उनके इस चरित्रको समझकर ही उनके व्यवहार और सिद्धांत को समझा जा सकता है। भारत के धार्मिक शहर बहुत अराजक और गंदे रहे हैं। विशेषकर उत्तर भारत में यह प्रवृत्ति धर्म का स्वरूप समझी जाती रही है और कहा जाता रहा है कि इसे धैर्यपूर्वक सहना चाहिए तभी पुण्यलाभ होता है। अयोध्या भी उससे परे नहीं रहा है। अयोध्या की तीर्थयात्रा पर जाने वाले वृद्ध लोग बताते हैं कि किस तरह रास्ते से लेकर शहर के मंदिरों में ठगी का कारोबार था। मंदिरों की मठाधीशी के लिए तो हत्याएं होना, हिंसा होना आम बात रही है। व्यापक समाज को आशा थी जिस राम मंदिर निर्माण को आजादी के आंदोलन के समतुल्य उपलब्धि के रूप में पेश किया गया उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा और एक नई सभ्यता के दर्शन होंगे। लेकिन स्वयं राम मंदिर में व्याप्त अराजकता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि संघ परिवार को आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर बर्चस्व कायम करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के अलावा धर्म के मूल्यों को स्थापित करने की रत्ती भर चिंता नहीं है। अगर संघ वास्तव में चरित्र निर्माण करने में यकीन करता तो उसके बड़े बड़े पदाधिकारी चढ़ावा चोरी में क्यों शामिल होते और वह क्यों कर उनका बचाव करता।

यहीं पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता आंदोलन का साभ्यतिक उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। गांधी सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह पर भारतीय लोगों का शासन आ जाए। वे इसलिए भी लड़ रहे थे कि भारतीयों का चरित्र इतना उज्जवल बने कि उनका शासन अंग्रेजी शासन से एकदम भिन्न हो। इसीलिए गांधी ने सात महापातकों कोगिनाते हुए उनसे भारतीयों को सचेत किया था और वे ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो इन बुराइयों से ऊपर हों। वे सात महापातक हैः-सिद्धांत के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना संपत्ति, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना ज्ञान और त्याग के बिना पूजा। आज आप संघ परिवार और उनके आनुसंगिक संगठनों पर दृष्टि डालें तो उनके अपंजीयन से लेकर चोरी और हिंसा की तमाम घटनाओं को देखकर यह सातोंपातक दिखाई पड़ेंगे।

इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष इन सात महापातकों से मुक्त है। विपक्ष अगर नैतिक और साहसी होता तो क्या देश और समाज की ऐसी स्थिति होती। न ही इसका यह अर्थ है कि भारतीय समाज और विशेषकर हिंदू समाज की संरचना इससे मुक्त होने का प्रयास कर रही है। इस समाज में गांव से राजधानी तक सार्वजनिक संपत्तियों को निजी उपयोग में लाने की भयानक बीमारी रही है। संघ ने उस निजी हित को अपने संगठन के हितों से जोड़ दिया और अपने को किसी जिम्मेदार और जवाबदेह संस्था के रूप में कायम करने के बजाय व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित कर लिया। उन्होंने इससे बड़ा पातक यह किया है कि राज्य की जो संस्थाएं स्वायत्त होती थीं और जिनका काम न्याय करना था, उन्हें अपना कारिंदा बना लिया है उनमें अन्याय को ही ऐतिहासिक न्याय के रूप में प्रतिष्ठित किया।

ऐसी स्थिति में नाउम्मीद होने से काम चलने वाला नहीं है। हम न तो राज्य को सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं और न ही धार्मिक समुदाय को। गांधी, लोहिया और आंबेडकर इन भी संरचनाओं में हस्तक्षेप करने और उन्हें सुधारने के हिमायती थे। निराशा के इस अंधकार के बीच बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश माधव जामदार अल्पसंख्यक समुदाय के एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जिलाबदर करने के फैसले को खारिज करके उम्मीद जगाते हैं। उम्मीद जगाती हैं नर्मदापुरम की जज तबस्सुम खान जो अपनी जान जोखिम में डालकर माब लिंचिंग के आरोपियोंको उम्र कैद की सजा देती हैं। खंडवा के जज अक्षय द्विवेदी भी अपनी सारी सरकारी सुविधाएं त्याग कर आशा जगाते हैं। उम्मीद पैदा करते हैं न्यायमूर्ति एस मुरलीधर जो इजराइल के अत्याचार को बेनकाब करते हुए फिलस्तीनी बच्चों की मौत पर दुनिया की अंतरात्मा को जगाते हैं। उम्मीद बनते हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जिन्होंने उज्जैन से अयोध्या तक की अराजनीतिक यात्रा का एलान किया है। उम्मीद जताते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिन्होंने इंडिया समूह की बैठक में प्रतिरोध को जमीन पर उतारने की घोषणा की है। उम्मीद जताते हैं अखिलेश यादव जिन्होंने अयोध्या के घोटाले को उजागर किया। उम्मीद हैं वे युवा जो शिक्षा प्रणाली मेंधांधली के विरुद्ध काकरोच जनता पार्टी बनाकर जंतर मंतर पर बैठे हैं और उम्मीद जताते हैं कि वे तमाम पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता जो मुख्यधारा से निष्कासित होने के बावजूद सच को सच कहने का साहस करते हैं। शायद वे ही असभ्यता की ओर जा रही भारतीयता को सभ्यता की ओर मोड़ सकते हैं।

अमारिला की टिप्पणी

बादल सरोज

लेखक लोकजतन के सम्पादक हैं।

ये गौरवर्ण की लुनाई इन्हीं से चुराई है

फुटबॉल मुकाबले के राउंड ऑफ़ 16 में पैराग्वे की हार के बाद बिफरी वहां की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे को लेकर बेहूदा नस्लीय टिप्पणियाँ की और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर अपमानजनक बातें कहीं। इसे लेकर स्वाभाविक ही था कि लोग खिन्न हुए, कुछ नाराज भी हुए, मगर जैसा कि होता है जल्दी ही इसे एक 'विवाद' बताया जाने लगा । एम्बाप्पे के जवाबी जुमले को अमारिला के आपराधिक शब्दों के बराबर रखकर पश्चिमी मीडिया अपना खेल खेलने लगा ।

कालों और अश्वेतों के प्रति यह द्वेष नया नहीं है बहुत पुराना है । लुटेरे जब इतिहास लिखते हैं तब सिर्फ इतिहास भर नहीं लिखते : वे भाषा भी गढ़ते हैं । मनुष्यता के शिकार में की गयी अपनी हिंसक, बर्बर, जघन्य और घोर आपराधिक ज्यादतियों पर पर्दा डालने के लिए भाषा को भी नुकीले खंजर की तरह वापरते हैं। दुष्टई को प्रचलन में लाकर आम बना देते हैं। जैसे जो चीज खराब है वह नियमतः काली होगी : काले क़ानून, काली करतूतें, कालिख पोत देना, मुंह काला कर देना । जिस तरह वर्चस्वकारी दर्शन और विचार वही होते हैं जो शासकवर्ग के होते हैं : इसी तरह भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ , कहावतें यहाँ तक कि व्याकरण भी वे ही कमबख्त तय करते हैं ।

हिन्दुस्तानियों - इस पूरे प्रायद्वीप - को यह याद दिलाने की जरुरत नहीं। अपने यहाँ की, किसी भी भाषा की गालियों, कहावतों पर निगाह डाल लीजिये पता चल जाएगा। उधर वाले कुंठित आत्ममुग्ध अमूमन रंग से खेलते हैं, इधर वालों के पास रंग के अलावा वर्ण है, जाति है, स्त्री है, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता और रोग भी हैं। सेलेस्टे अमारिला के मुंह से निकला गरल इसी का प्रवाह था।

मगर मादाम यह भूल गयी कि सत्य वह होता है जो तथ्यों में दर्ज और खुली आँखों से दृष्टव्य होता है । वे यह भी भूल गयीं कि जिस एम्बाप्पे की अफ्रीकी देशों से जुड़ी जड़ें उन्हें चुभ रहीं हैं। कैमरून के पिता और अल्जीरिया की माँ का बेटा होना इन्हें उसके कमतर होने का आधार नजर आ रहा है - वह एम्बाप्पे अकेला नहीं है । बहुत पहले कभी तब तक की फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी पेले ने कहा था कि इस शताब्दी के अंत तक कोई अफ्रीकी देश फुटबॉल विश्वकप जीतकर जाएगा। उनका कहा उस तरह तो नही किंतु कुछ इस तरह सच हुआ कि पूरा फीफा वर्ल्ड कप ही अफ्रीकियों और प्रवासियों का होकर रह गया।

डियागो माराडोना ने 2018 के विश्वकप को 'अब तक का सर्वाधिक आप्रवासी खिलाड़ियों वाला विश्व कप' बताया था। विस्तार से बचने के लिए पुराने उदाहरणों को गिनाने की बजाय इसी - फीफा 2026 -मुकाबले को ले लेते हैं और राउंड ऑफ़ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची 8 टीमों के प्रोफाइल पर ही नजर डाल लेते हैं ।

फ्रांस से ही शुरू करते हैं। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को पर किलियन एम्बाप्पे के अलावा जिन उस्मान डेम्बेल ने गोल दागा था उनके पिता माली से और उनकी माँ मॉरिटानिया और सेनेगल मूल की हैं। फ्रांस की 26 सदस्यीय टीम में से 21 खिलाड़ी अफ्रीकी हैं या मिश्रित हैं या काले हैं । 2018 की फ्रांस की विश्व विजेता टीम के 14 खिलाड़ी और 2022 की टीम के 13 खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के थे। अल्जीरिया, कैमरून,अंगोला, कांगो, बेनिन, गिनी बिसाऊ, माली, मोरक्को,सेनेगल और मॉरितानिया आदि देश उनका मूल उदगम थे। इस बार इनकी संख्या और बढ़ी ही है 26 में से 21 हो गयी है ।

जिस मोरक्को को उन्होंने हराया उसके 26 में 19 खिलाड़ी विदेशों में जन्मे हैं। इनमे एक को छोड़ दें तो 18 खिलाडीआप्रवासी हैं : डायस्पोरा हैं । बाहर से आये हैं। इनके कप्तान और शानदार खिलाडी अशरफ हकीमी स्पेन में जन्मे हैं । फ्रांस में जन्मे 6, नीदरलैंड और बेल्जियम में जन्मे 3-3 हैं ।

अभी अभी सुबह शानदार खेल के बाद भी क्वार्टर फाइनल हारे स्विट्ज़रलैंड का हाल और भी निराला है। इनके 2 खिलाड़ी कैमरून,1 इंग्लैंड का है । इतना ही नहीं बाकी 23 खिलाडियों के रोस्टर का 90% उन खिलाडियों से बना है विदेशी मूल के हैं ।

आज ही इंग्लैंड से हारी नॉर्वे के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मोरक्को, कोटे डी आइवर,गाम्बिया, वियतनाम और नाईजीरिया से ताल्लुक रखते हैं। इंग्लैंड के 26 में से 15 खिलाड़ी या तो अफ्रीकी मूल के हैं या कैरबियन देशों से आये हैं। अपने गोरेपन पर गुरियाने वाले अंग्रेज अपने ही देश की टीम में अल्पमत में हैं।

स्पेन तक की टीम में 2 अश्वेत अफ्रीकी हैं । इसके लातिन अमरीका के पूर्व उपनिवेशों के मूल वाले खिलाड़ियों की सूची निकालेंगे तो बोलिविया से मैड्रिड तक सीमोन द बोलिवर की संतानों की खटियायें बिछ जायेंगी।

बेल्जियम की टीम में सेनेगल के एमाडोऊ ओनामा सहित 9 खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के हैं।

सिर्फ अर्जेंटीना ऐसी टीम है जिसमे इटली में जन्मे सिमेओन और अर्जेंटीनी माँ बाप से मैड्रिड में जन्मे निकोलस पाज़ को छोड़कर बाकी सभी अर्जेंटीनी हैं । अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अश्वेत खिलाड़ियों की अनुपस्थिति कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक इस देश के नृशंस इतिहास से जुड़ा हुआ है। 19वीं और 20वीं सदी के अंत में, अर्जेंटीना के तानाशाहों ने बड़े पैमाने पर यूरोपीय प्रवासियों को न्यौता और गैर यूरोपीय यहाँ तक कि लैटिन अमरीका के ही नागरिकों को खदेड़ा : नरसंहार भी किये गए। नतीजे में देश की अश्वेत आबादी का प्रतिशत काफी कम हो गया, जिसका प्रभाव आज की खेल टीमों में भी दिखाई देता है।

बहरहाल ओलंपिक्स के सारे खेलों से लेकर सारे फुटबॉल मुकाबलों में इन देशों की टीम्स देख लीजिए। फीफा की 8 टीमों की विवरणिका ऊपर दी है, बाकी के भी यही हाल हैं। यूरोप हो या अमरीका का संयुक्त राज्य अमरीका - गोरे रंग पे गुमान करने वाला कोई भी देश बिना कालों के एक मैच नहीं जीत सकता।

इसके बाद भी इन आप्रवासी खिलाड़ियों का महेरी में साझे खीर में न्यारे का दर्द है। पिछले विश्वकप के बाद लुकाकु अपने ब्लॉग में लिख चुके हैं कि 'जब मैं अच्छा खेलता हूँ तो मुझे बेल्जियन स्ट्राइकर कहा जाता है, जब नही खेल पाता तो मेरा परिचय कांगो मूल के बेल्जियम खिलाड़ी का रह जाता है।' इतने ही पाखंडी हैं ये नस्लवादी!!

यह सच आज जोर से दोहराना जरूरी है। क्योंकि इन्ही देशों के कुछ नेता अपने देश केआप्रवासियों के खिलाफ जहरीली मुहिम छेड़े हुए हैं। हिन्दुस्तान की तरह ये देश भी कारपोरेट की गोद मे बैठी नव-नाजीवादी, फासिस्टी, रंगभेदवादी, नस्लवादी संकीर्ण राजनीति और ओछे ठगों की चपेट में हैं। अमारिला मैम, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए महिला होने की आड़ मत लीजिये। आपकी टिप्पणी के जवाब में एम्बाप्पे ने 'घृणित महिला, जो जिस पद पर है उस पद के योग्य नहीं है' कहा। आप की जगह कोई पुरुष होता तो वह घृणित महिला की जगह आदमी बोलता। इसमें जेंडर नहीं क्लास है ।

सदियों तक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमरीका के देशों, उनकी संपदा की चोरी और उनके नागरिकों की गुलामी के दम पर खड़ी हुयी हैं यूरोप और ट्रम्प वाले अमरीका की अट्टालिकाएं। आज भी उनकी चमचमाहट में न जाने कितनी पीढ़ियों का खून शामिल है। अमीर देश और उनके अमीर क्लब्स अफ्रीका से सिर्फ सोना-हीरा-खनिज और सम्पदा चुराकर ही नहीं ले जाते। इन अफ्रीकियों की देह के बल के दम पर खिताब भी जीतते हैं। यही देश आज भी इन्ही पूर्व-गुलामो और उनके आज के वंशजो की मेहनत और ताकत के दम पर मजे उड़ा रहे हैं ।

हमारे यहाँ एक निराले कवि हुए हैं, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, वे आप और आप जैसों को संबोधित करते हुए कह गए हैं कि 'अबे सुन बे गुलाब/भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब/रक्त चूसा खाद का तूने अशिष्ट/डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट'।

फीफा के चमचमाते स्टेडियम्स, होटल, सड़कों, वाशरूम्स, खिलाड़ियों और दर्शकों की देखरेख जैसे अनदिखे कामों के पीछे भी आप्रवासी मजदूरों का श्रम है । इनमे विराट बहुमत उनका है जो यूंही यहां वहां काम करते भटक रहे हैं । फीफा कुछ हजार करोड़ कमाएगा, टेलीकास्ट करने वाली कंपनिया और मीडिया भी करोड़ों अपनी अन्टी में डालेगा। मगर इस मुनाफे को उजाला देने वालों में आप्रवासी मजदूरों का 80-85% हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें न न्यूनतम वेतन देना पड़ता है, न किसी जोखिम से बचाव की गारंटी ।

यहां खेल से द्वेष नहीं है -फुटबॉल से तो किसी भी तरह का मलाल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मगर जब उसके बहाने अफ्रीकियों, एशियाइयों, लातिनी अमरीकियों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें तंज़ मारा जाता है तो बदरंग को बदरंग कहना जरूरी हो जाता है। रोशनी के स्वयंभू ठेकेदारों की रोशनी के उन स्रोतों को देखना जरूरी हो जाता है जिन्हे अँधेरे में पहुंचा कर तिलिस्मी चौंध हासिल की गयी है।

भोपाल के शायर फज़ल ताबिश कह गए हैं कि जो दिख रहा है उससे चमत्कृत होने की बजाय; 'रेशा रेशा उधेड़ कर देखो/रोशनी किस जगह से काली है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

नंदकिशोर बर्वे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चंदा ओ चंदा तेरे रूप अनेक, सब कितने मनमोहक

शब्दकोश कहता है कि चाँद और चंदा एक ही चीज़ है। दोनों की राशि तो एक है, ही उनका भाव और स्वरुप भी एक ही है। फिर भले ही मात्र मात्रा का फर्क हो, ज्यादा न सही थोड़ा हो, पर होता है। चाँद की सोलह घोषित कलाएं होती हैं। लेकिन चंदा की कलाओं की कोई सीमा नहीं होती। कुछ नादान चंदा को सीमाओं में बांधना चाहते हैं। वे अपने प्रयास करते रहें। जब कभी निराश होने लगें तो चंदा से जो अमृत बरसता है, उसका आस्वादन कर सकें तो करें, और अपने मिशन में लगे रहें।

हम चंदा के विभिन्न स्वरुप सदियों से सुनते देखते आयें हैं। और अपने जीवन काल में तो देखते ही हैं। हालाँकि शहरी चकाचौंध और आपाधापी के साथ ही हम जो अपनी दुनिया मुट्ठी में करे बैठे हैं, उस कारण हमें चंदा देखने की फुर्सत किधर है? फिर भी जब कभी रील या अख़बारों में चंदा का जिक्र होता है, तब हम ज़रूर उसकी तरफ़ ध्यान धरते हैं। वरना चंदा अपनी कलाएं बिखेरता रहता है, और हम अपने में लगे हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

अमावस के बाद जब पड़वा का नन्हा सा चंदा निकलता है, तो कितना प्यारा सा होता है। फिर वह क्रमशः बढ़ने लगता है। और होने वाले उस पर मोहित होते रहते हैं। उसकी रोशनी और शीतलता दोनों बढ़ती जाती है। और उसी अनुपात में उसका आनंद लेने वाले भी। फिर चंदा हर दिन बढ़ता है। चाँद तो पूरनमासी को प्राप्त करके फिर घटने लगता है। लेकिन चंदा ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ता। उसका एकमात्र जीवन दर्शन बस बढ़ते रहना होता है। सो वह बढ़ता है। हर दिन हर स्तर पर बस चंदा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। ईवन स्काई इज़ नाट द लिमिट' वह खुद से कहता है। वो दिन हवा हुए जब चंदा की कोई सीमा होती थी। अब अनंत सम्भावनाएं हैं। और अवसर भी। जो कर गुजरने वालों की योग्यता पर निर्भर हैं।

चंदा की शोभा छोटे छोटे सितारों से होती है। आप कल्पना कीजिये कि चंदा अकेला हो और सितारे न हों तो कैसा सूना सूना सा लगेगा यह जहाँ। इसलिए चंदा कभी अकेला नहीं होता उसकी रौशनी से छोटे बड़े तमाम सितारे लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि एकाध दिन अमावस के कारण चंदा छुट्टी पर होता है, तब भी सितारे अपना काम करते रहते हैं। उनकी निरन्तरता स्तुत्य है।

शरद पूर्णिमा के दिन अपनी छत पर जो खीर/दूध का बर्तन रखकर उसमें अमृत वर्षा की बात तो आप बहुत गर्व से करते हो। बड़े नादान हो। एकदम बिल्कुल अबोध हो यार। जो जानकार हैं, वे प्रतिदिन अपना पात्र चंदा का अमृत पाने के लिए खुला रखते हैं। चंदा भी कहता है, कि जो अपना पात्र खुला रखेगा उसी में तो अमृत वर्षा होगी। एक तो अपना पात्र खुला नहीं रखते हो, और फिर शिकायत करोगे कि देखो उसके पात्र में चंदा का कितना अमृत है। यूँ भी दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखने की परम्परा हमेशा से रही है।तो भइये मैं पूछता हूँ, आपको किसने मना किया है, अपना पात्र खुला रखने से। रखो। अब तुम कहोगे कि हमारा ज़मीर इस बात कि स्वीकृति नहीं देता। तो बैठे रहो अपने ज़मीर के साथ। अब जो चीज़ सहज ही उसकी चाह रखने वालों को मिल रही है, वह भी आपको नहीं चाहिए,तो इसमें चंदा का क्या दोष ?

चंदा की अपनी शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना भी। बोले तो सभी तरह की। चंदा की व्यंजना हमेशा से मारक भी रही है। और साथ ही तारक भी। चंदा में आदमी पहले तरता है। फिर उसके पीछे वे लोग पड़ जाते हैं। जिनसे कुछ बनता नहीं। फिर भी जब तक लोग कुछ समझें, तब तक वह पर्याप्त तर चुका होता है। पर लोग समझते नहीं हैं कि आख़िरकार चंदा कितना ऊँचा होता है, हर किसी ऐरे गैरे की कोई पहुँच है भी, उस तक। हालाँकि इन लोगों के चिल्लाने से उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वह तो अपने उद्देश्य में पूरे मनोयोग से लगा रहता है। ऐसे हर किसी के कहने से चंदा के आनंद में तैरने वाला बंदा चिंतित होता रहे तो फिर तो बस ले लिया आनंद।

तो चंदा का लब्बोलुआब यही निकलकर सामने आया कि इसमें जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होते हैं, उनको मुन्नाभाई की तरह लगे रहना होता है। और वे लगे रहते भी हैं। आप अपना काम करो और उनको उनका करने दो बस। बात ख़लास।

क्या इंसान भी विकास का हिस्सा है?

विकास तभी सार्थक है, जब उसकी कीमत किसी की पहचान, आजीविका और अस्तित्व न बने। आज भारत इसी प्रश्न के सामने खड़ा है। एक ओर देश की पहली नदी जोड़ो योजना के रूप में केन-बेतवा परियोजना है, जिसे जल, सिंचाई और ऊर्जा का समाधान बताया जा रहा है। दूसरी ओर पन्ना और छतरपुर के जंगलों में आदिवासी महिलाएँ चिता पर लेटकर, शरीर पर मिट्टी मलकर केवल दो वाक्यों में अपना दर्द कह रही हैं- 'जंगल हमारा, नदी हमारी' और 'न्याय दो या मार दो।' यह केवल विरोध नहीं, लोकतंत्र पर टूटते भरोसे की तस्वीर है। अब सवाल बाँध बनने का नहीं, बल्कि यह है कि विकास की परिभाषा आखिर किसके लिए लिखी जा रही है।

केन-बेतवा परियोजना

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक शिक्षाविद् हैं।

केन-बेतवा परियोजना का प्रमुख हिस्सा दौधन बाँध है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर प्रस्तावित है। इससे लगभग 9 हजार हेक्टेयर भूमि, जिसमें कोर क्षेत्र का करीब 41.41 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र शामिल हैं, डूबेगी। करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है।

वादों और ज़मीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है। सवाल है–यदि विकास की कीमत आदिवासी समाज चुकाए और लाभ दूसरों को मिले, तो क्या यह न्यायपूर्ण विकास कहलाएगा?

इस संघर्ष का दायरा केवल विस्थापन नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका है, जिससे बाघों की पुनर्स्थापना, घड़ियाल संरक्षण और गिद्धों के प्राकृतिक घोंसले संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्ष कटाई और पारिस्थितिकी परिवर्तन से क्षेत्रीय वर्षा में करीब 12 प्रतिशत कमी आ सकती है। केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक भी इसके प्राकृतिक तंत्र पर प्रभाव की चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए आदिवासियों का 'जंगल हमारा, नदी हमारी' कहना विकास विरोध नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की चिंता है।

किसी भी विस्थापन की सबसे बड़ी कीमत आँकड़े नहीं, इंसानी ज़िंदगियाँ चुकाती हैं। केन-बेतवा परियोजना भी इसी सच्चाई के सामने है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 7 हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे और 22 गाँव डूब क्षेत्र में समा जाएँगे। पुनर्वास को लेकर असंतोष है। किसी को साढ़े बारह लाख, तो किसी को केवल साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा मिल रहा है। वयस्क सदस्यों को अलग परिवार का दर्जा देने की माँग अधूरी है। आदिवासी समाज नकद नहीं, 'भूमि के बदले भूमि' चाहता है, क्योंकि जंगल और खेत उसके जीवन का आधार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। पर्याप्त सूचना बिना मकान तोड़े जाने से प्रशासन और समाज के बीच भरोसे की खाई गहरी हुई है।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी अहम है। सरकार का तर्क है कि भविष्य की जल जरूरतों के लिए बड़े समाधान जरूरी हैं। सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि किसी परियोजना का मूल्य केवल लाभ से तय होगा या उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत से भी। केन-बेतवा परियोजना ने फिर बहस छेड़ी है कि नदी जोड़ो योजनाएँ तभी सफल होंगी, जब वे स्थानीय परिस्थितियों, पारिस्थितिकी और समाज की जरूरतों के अनुरूप हों। केवल इंजीनियरिंग समाधान, प्रकृति और समुदाय की सहमति बिना, स्थायी नहीं हो सकते। विकास तभी सार्थक है, जब लाभ और कीमत का न्यायपूर्ण संतुलन हो।

बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे, टिकाऊ विकल्प भी जरूरी हैं। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, जलग्रहण प्रबंधन और स्थानीय जल संरक्षण को बेहतर समाधान मानते हैं। सवाल है कि मध्य प्रदेश अपने जंगलों, वन्य संपदा और जल संसाधनों की कीमत चुका रहा है, जबकि लाभ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने भी परियोजना की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवहार्यता पर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की थीं, लेकिन उन्हें महत्व नहीं मिला। यदि बड़े निर्णयों में वैज्ञानिक चेतावनियाँ, स्थानीय अनुभव और न्यायपूर्ण पुनर्वास उपेक्षित रहें, तो विकास का दावा संदेह के घेरे में आता है। लोकतंत्र की शक्ति केवल निर्णय में नहीं, असहमति सुनने में भी है।

पन्ना और छतरपुर से उठता यह संघर्ष अब केवल कुछ गाँवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि भारत का विकास प्रकृति और मानव के संतुलन के साथ होगा या जंगलों और संस्कृतियों की कीमत पर। आदिवासी महिलाओं का संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि सम्मान, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का है। सरकार को पारदर्शी पुनर्वास, प्रभावी पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान के तहत 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन विकास प्रस्तावित है। इतिहास बाँधों की ऊँचाई नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों के साथ राष्ट्र के व्यवहार को याद रखता है। विकास तभी टिकाऊ होगा, जब वह प्रकृति और लोगों की सहमति से आगे बढ़े।

थोड़ा बाहर तो निकलिये जनाब

मानसून और मौसम के जानकार कुछ भी भविष्यवाणी कर दें हमारे यहां किसान भाइयों का अपना गणित, अपना पूर्वानुमान तथा अपना खुद का आकलन रहता है। हमारे यहां प्रचलित पंचांग भी सटीक अनुमान ही बतलाते हैं। सो, एक पखवाड़े पहले ही किसानों ने खरीफ फसलों के लिये जरूरी तैयारियां कर ली थी। मानसून पूर्व बारिश के चलते अनेक जगह बोवनी शुरू हो चुकी थी। अब खेतों में फसलें अंकुरित हो चली हैं तो कहीं और भी ज्यादा बढ़वार दिखाई दे रही है।

दृष्टिकोण

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

बीते दस- बारह दिन से प्रकृति बड़ी मेहरबान है और हमारे प्रदेश में तकरीबन सभी जगह मानसून ने दस्तक दे दी है। तमाम अनुमानों को धता बताते हुए फिलहाल तो कृपा बरस रही है आगे भी अच्छा रहेगा यह उम्मीद की जा सकती है। प्रकृति कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। समय चक्र के साथ उसका भी पहिया घूमता रहता है। सो, इस बार मानसून भले ही विलम्ब से आया लेकिन दुरुस्त आया यह कहा जा सकता है।

मानसून और मौसम के जानकार कुछ भी भविष्यवाणी कर दें हमारे यहां किसान भाइयों का अपना गणित, अपना पूर्वानुमान तथा अपना खुद का आकलन रहता है। हमारे यहां प्रचलित पंचांग भी सटीक अनुमान ही बतलाते हैं। सो, एक पखवाड़े पहले ही किसानों ने खरीफ फसलों के लिये जरूरी तैयारियां कर ली थी। मानसून पूर्व बारिश के चलते अनेक जगह बोवनी शुरू हो चुकी थी। अब खेतों में फसलें अंकुरित हो चली हैं तो कहीं और भी ज्यादा बढ़वार दिखाई दे रही है।

बीते मंगलवार को भोपाल से इंदौर की यात्रा के दौरान जो दृश्य दिखाई दिये उससे मन प्रफुल्लित हो उठा। भोपाल के नज़दीक मुगालिया छाप के आसपास खेत पानी से भरे हुए थे तो कहीं धान की रोपाई चल रही थी या कहीं हो चुकी थी। नीलबड़-रातीबड़ के समीप से लेकर खजूरी सड़क से हाईवे पर सीहोर, कोठरी, आष्टा, डोडी, सोनकच्छ, देवास और इंदौर तक खेतों में पानी भरा हुआ था और हरी- भरी फसलें उग आई थी। कमोबेश सभी जगह ऐसा ही दृश्य देखने में आया। उम्मीद है प्रदेश में अन्य जगहों तथा अन्य राज्यों (अपवाद स्वरूप छोड़कर) में भी यही स्थिति निर्मित हुई होगी। हालांकि,खबरें यह भी आ रही है कि पिछले तीन-चार दिनों से बादल तो छा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। उम्मीद है जल्द बादल उमड़ घुमड़ कर बरसेंगे।

हम कितनी भी बड़ी- बड़ी बातें कर लें लेकिन आज भी देश का कृषि सेक्टर हमारी अर्थ व्यवस्था का प्रमुख कारक है। हरे-भरे खेत और किसानों के चेहरों पर खुशी देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा। इस यात्रा के दौरान जो फिक्र सामने आई वो थी कि धीरे- धीरे खेती का रकबा घटता क्यों जा रहा है? उसकी जगह राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक जगह-जगह खेतों पर कहीं- कहीं पर भव्य इमारतें तो कहीं मैरिज गार्डन , रिसॉर्ट, होटल्स आदि तनते जा रहे हैं। निश्चित ही यह चिंता की विषय होना चाहिये। इस बात का हिसाब किताब तो होना चाहिये कि हाल के वर्षों में खेती योग्य कितनी जमीन पर कमर्शियल गतिविधियां शुरू की गई है। क्या कुछेक किसानों, खासकर नई पीढ़ी के युवाओं का खेती से मोहभंग तो नहीं होता जा रहा है? अगर ऐसा है तो इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देकर किसान परिवारों के युवाओं को खेती- किसानी की ओर उन्मुख करने की दिशा में एक रणनीति के तहत काम करना चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसानों को जरूरत के खाद बीज समेत अन्य कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्हें यूरिया आदि खाद और बीज के लिये भटकने नहीं दिया जाना चाहिये, ऐसे प्रबंध नितांत आवश्यक है। हालांकि इस बार वैश्विक परिदृश्य, युद्ध की स्थिति को लेकर अनिश्चितता के चलते खाद (यूरिया) की किल्लत स्वाभाविक रूप से सामने आई। अच्छा होगा भविष्य के लिये रणनीति बनाकर तदनुरूप प्रयास किये जायें।

सो, बड़े शहरों के सुविधाभोगी लोगों को शहर से बाहर निकलकर भी इस मौसम में सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों के साथ खेती - किसानी के हालात की जानकारी लेते रहना चाहिये। महज अपनी जरूरत के गेहूँ, दाल-भात, सब्जियां शहर में बैठे- बिठाये खरीदने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो सकती बल्कि इन्हें आप तक पहुंचाने में कितना लंबा और थकाऊ प्रोसेस चलता है इस बात से अवगत तथा अवेयर होना भी आज की जरूरत है। आखिर तेजी से बढ़ता शहरीकरण धीरे- धीरे खेती की ओर उपेक्षा के भाव का विस्तार ही तो नहीं कर रहा, यह देखना सरकारों के साथ जागरूक नागरिकों का भी कर्तव्य है।

सामरिक प्रभुत्व निर्धारित करता है निर्माण कार्यों की गति

**इन दिनों बांग्लादेश के द्वारा मोंगला पोर्ट के विनिर्माण विकास अधिकार भारत से वापस लेकर, चीन को सौंपे जाने की चर्चाएं चहुंओर हो रही है। कारणों में ,वर्ष 2024 शेख हसीना सरकार के निष्काषन को प्रधान्यता के साथ उठाया गया, लेकिन इस शोर में हमने उस तथ्य का वेष्टन किया है, जो हमारे क्रियान्वयन के घोंघा चाल से उजागर होता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के तहत, तय हुए अनुबंध में, भारत को 110 एकड़ क्षेत्र पर आर्थिक गलियारे को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था । भारत की सुस्पष्ट लाइन ऑफ क्रेडिट योजना से इसका वित्तपोषण होना था। इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत निर्माण सामान व सेवाएं भारत से प्राप्त करना होता है। भारत सरकार से सरकार (जी टू जी) स्तर पर हुए, मोंगला पोर्ट विकास समझौते को मूर्त रूप देने के लिए एक लंबी जटिल कागजी कार्रवाई चली, जिसके बाद सन 2018 में भारत सरकार से फंड जारी हुआ । बांग्लादेश की ओर से 2019 में सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के संबंध में कड़े प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया। जिनमें कंसल्टेंसी समूहों से ऊँचे टर्न ओवर, नेटवर्थ, वृहद् कार्यक्षेत्र और विशिष्ट तकनीकी अनुभव की माँग अपेक्षित की गई । इन शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में, अडानी ग्रुप और एल. एन. टी. समूह को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी समूह सक्षम नहीं थे। योग्यता के बावजूद इन दोनों बड़े समूहों का भागीदारी न दिखाना, तात्कालिक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों, लाभांश और सीमित स्वतंत्र कार्यशैली के वजह से था। विपक्ष, सरकार पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के आरोपों के साथ हावी था, स्वयं अडानी समूह भी इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा हीरानंदानी ग्रुप को नामित कर देने के बाद सलाहकार फर्म के तौर पर, मात्र 80 करोड़ के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने को इच्छुक न था। जबकि एल.एन.टी. समूह लाइन ऑफ क्रेडिट जैसी योजनाओं की बाध्यकारी नियमावली में कार्य करने के बजाए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भरोसा रखता है। इस सब का अंततोगत्वा परिणाम यही निकला कि 9 वर्षों के लम्बे विलंब और 2024 में शेख हसीना सरकार के निष्कासन के साथ उपजी भारत विरोधी भावनाओं में मोंगला पोर्ट के विकास अधिकार चीनी सरकारी कम्पनियों के ओर बह गए।

पड़ोसी देशों में रणनीतिक महत्व वाले स्थानों पर

पिछड़ते भारतीय प्रोजेक्ट हमारी वैश्विक कूटनीतिक बढ़त को बेहद कमजोर कर देते हैं। उदाहरण सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं है,म्यांमार में वर्ष 2008 में स्वीकृत और 2010 से कार्यरत कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की एकमात्र पहुंच को वैकल्पिक मार्ग देता है। शिथिल कार्यशैली के चलते यह प्रोजेक्ट भी तय समय सीमा, वर्ष 2014 तक पूरा न हो सका। इसके बाद 2019 में कोरोना महामारी और म्यांमार में साल 2021 के सैन्य तख्ता पलट से निर्मित अनिश्चितताओ के चलते, यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज भी पूर्ण होने की राह देख रहा है। म्यांमार से जुड़ा एक और अहम, भारत - म्यांमार - थाईलैंड राजमार्ग का कार्य , 2002 में विचारित, 2012 से आरंभित और 2016 को पूर्णता के प्रति लक्षित था। भारत इसे कंबोडिया,लाओस व वियतनाम तक प्रसारित कर ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूप देना चाहता है , हाल फिलहाल यह आशंकाओं से घिरा है । वहीं चीन इसके समानांतर सीमेक (चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर) के प्रतिस्पर्धी निर्माण में लगा है । भारत द्वारा भूटान में मांगदेछू और पुनातसांगछु - II जैसी पनबिजली परियोजनाओं को पूरा करने में क्रमशः 9 वर्ष और 15 वर्ष का लंबा समय लगा था। वहीं पुनातसांगछु - I परियोजना, भूस्खलन और तकनीकी विरोधाभासो से जूझते हुए, लगभग 21 वर्षों बाद पूर्णतः संचालित हो सकेंगी। जबकि इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए, चीन अपनी उन्नत अत्याधुनिक तकनीक जैसे मेगा टी.बी.एम. मशीन, सेटेलाइट मैपिंग, 3डी जी.आई. एस. मॉडलिंग द्वारा कमजोर चट्टानों की पहचान, स्खलन के बाद हाई स्पीड केमिकल ग्राउटिंग और रोबोटिक्स इंफोर्समेंट की मदद से, यह सभी निर्माण कार्य 7 से 9 वर्षों में पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है।

सामरिक हितों के यह प्रोजेक्ट सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत में भी निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक विकास, अरुणाचल में चीन की चुनौतियों के जवाब में प्रस्तावित कमला,दिबांग, कलई जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जिनका समय अवधि में पूरा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्णायक रहेगा। निर्माण कार्यों की देरी, लागत में तो बढ़ोतरी करती ही है, अनिश्चित भौगोलिक विपदाओं की पुनरावृत्ति को अधिक अवसर देती है, साथ ही तेजी से बदलते वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने का स्थान सौंपती है। आज भारत सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के पंच सिद्धांतों पर आधारित 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'लूक ईस्ट' पॉलिसी को मान्यता देता है। अपेक्षाकृत अधिक भागीदारीपूर्ण, सुरक्षित और किफायती होने के बावजूद यह भारतीय योजनाएं , पड़ोसी देशों में अपनी जटिल प्रक्रिया व दीर्घ कार्यावधि के कारण चीन की आक्रामक, महंगी लेकिन तेज निर्माण गति वाली बी.आर.आई जैसी योजनाओं से पिछड़ती नजर आती है। आवश्यक है कि, इन विषमताओं का सामना भारत सरकार प्रक्रियाओं को सरल व त्वरित बना कर एवं निर्माणाधीन कंपनियां लाभांश के अनुपातिक आंकलन से ऊपर उठकर राष्ट्रहितों के अनुकूल सैन्य चपलता से करें।

सामयिक

विवेक मिश्रा

वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के तहत, तय हुए अनुबंध में, भारत को 110 एकड़ क्षेत्र पर आर्थिक गलियारे को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था । भारत की सुस्पष्ट लाइन ऑफ क्रेडिट योजना से इसका वित्तपोषण होना था। इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत निर्माण सामान व सेवाएं भारत से प्राप्त करना होता है।

भारत सरकार से जारी फंड की प्राप्ति पर, संबंधित देश औपचारिक निविदा जारी कर आवंटन करते हैं। सरकार से सरकार (जी टू जी) स्तर पर हुए, मोंगला पोर्ट विकास समझौते को मूर्त रूप देने के लिए एक लंबी जटिल कागजी कार्रवाई चली, जिसके बाद सन 2018 में भारत सरकार से फंड जारी हुआ । बांग्लादेश की ओर से 2019 में सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के संबंध में कड़े प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया। जिनमें कंसल्टेंसी समूहों से ऊँचे टर्न ओवर, नेटवर्थ, वृहद् कार्यक्षेत्र और विशिष्ट तकनीकी अनुभव की माँग अपेक्षित की गई । इन शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में, अडानी ग्रुप और एल. एन. टी. समूह को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी समूह सक्षम नहीं थे। योग्यता के बावजूद इन दोनों बड़े समूहों का भागीदारी न दिखाना, तात्कालिक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों, लाभांश और सीमित स्वतंत्र कार्यशैली के वजह से था। विपक्ष, सरकार पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के आरोपों के साथ हावी था, स्वयं अडानी समूह भी इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा हीरानंदानी ग्रुप को नामित कर देने के बाद सलाहकार फर्म के तौर पर, मात्र 80 करोड़ के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने को इच्छुक न था। जबकि एल.एन.टी. समूह लाइन ऑफ क्रेडिट जैसी योजनाओं की बाध्यकारी नियमावली में कार्य करने के बजाए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भरोसा रखता है। इस सब का अंततोगत्वा परिणाम यही निकला कि 9 वर्षों के लम्बे विलंब और 2024 में शेख हसीना सरकार के निष्कासन के साथ उपजी भारत विरोधी भावनाओं में मोंगला पोर्ट के विकास अधिकार चीनी सरकारी कम्पनियों के ओर बह गए।

पड़ोसी देशों में रणनीतिक महत्व वाले स्थानों पर

पिछड़ते भारतीय प्रोजेक्ट हमारी वैश्विक कूटनीतिक बढ़त को बेहद कमजोर कर देते हैं। उदाहरण सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं है,म्यांमार में वर्ष 2008 में स्वीकृत और 2010 से कार्यरत कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों की एकमात्र पहुंच को वैकल्पिक मार्ग देता है। शिथिल कार्यशैली के चलते यह प्रोजेक्ट भी तय समय सीमा, वर्ष 2014 तक पूरा न हो सका। इसके बाद 2019 में कोरोना महामारी और म्यांमार में साल 2021 के सैन्य तख्ता पलट से निर्मित अनिश्चितताओ के चलते, यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज भी पूर्ण होने की राह देख रहा है। म्यांमार से जुड़ा एक और अहम, भारत - म्यांमार - थाईलैंड राजमार्ग का कार्य , 2002 में विचारित, 2012 से आरंभित और 2016 को पूर्णता के प्रति लक्षित था। भारत इसे कंबोडिया,लाओस व वियतनाम तक प्रसारित कर ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूप देना चाहता है , हाल फिलहाल यह आशंकाओं से घिरा है । वहीं चीन इसके समानांतर सीमेक (चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर) के प्रतिस्पर्धी निर्माण में लगा है । भारत द्वारा भूटान में मांगदेछू और पुनातसांगछु - II जैसी पनबिजली परियोजनाओं को पूरा करने में क्रमशः 9 वर्ष और 15 वर्ष का लंबा समय लगा था। वहीं पुनातसांगछु - I परियोजना, भूस्खलन और तकनीकी विरोधाभासो से जूझते हुए, लगभग 21 वर्षों बाद पूर्णतः संचालित हो सकेंगी। जबकि इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए, चीन अपनी उन्नत अत्याधुनिक तकनीक जैसे मेगा टी.बी.एम. मशीन, सेटेलाइट मैपिंग, 3डी जी.आई. एस. मॉडलिंग द्वारा कमजोर चट्टानों की पहचान, स्खलन के बाद हाई स्पीड केमिकल ग्राउटिंग और रोबोटिक्स इंफोर्समेंट की मदद से, यह सभी निर्माण कार्य 7 से 9 वर्षों में पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है।

सामरिक हितों के यह प्रोजेक्ट सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत में भी निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक विकास, अरुणाचल में चीन की चुनौतियों के जवाब में प्रस्तावित कमला,दिबांग, कलई जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जिनका समय अवधि में पूरा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्णायक रहेगा। निर्माण कार्यों की देरी, लागत में तो बढ़ोतरी करती ही है, अनिश्चित भौगोलिक विपदाओं की पुनरावृत्ति को अधिक अवसर देती है, साथ ही तेजी से बदलते वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने का स्थान सौंपती है। आज भारत सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के पंच सिद्धांतों पर आधारित 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'लूक ईस्ट' पॉलिसी को मान्यता देता है। अपेक्षाकृत अधिक भागीदारीपूर्ण, सुरक्षित और किफायती होने के बावजूद यह भारतीय योजनाएं , पड़ोसी देशों में अपनी जटिल प्रक्रिया व दीर्घ कार्यावधि के कारण चीन की आक्रामक, महंगी लेकिन तेज निर्माण गति वाली बी.आर.आई जैसी योजनाओं से पिछड़ती नजर आती है। आवश्यक है कि, इन विषमताओं का सामना भारत सरकार प्रक्रियाओं को सरल व त्वरित बना कर एवं निर्माणाधीन कंपनियां लाभांश के अनुपातिक आंकलन से ऊपर उठकर राष्ट्रहितों के अनुकूल सैन्य चपलता से करें।

छात्रावासों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें : कलेक्टर

जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतें

पेयजल स्रोतों की नियमित सफाई व क्लोरीनेशन करें

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, लोक निर्माण, वाणिज्यिक कर, सामाजिक न्याय एवं श्रम विभाग सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टाइम-लिमिट एवं जनसुनवाई के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। लोक सेवा गारंटी के समय-सीमा से बाहर गए प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जिले के सभी छात्रावासों में ई-लर्निंग टूल्स एवं लाइब्रेरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला परियोजना समन्वयक को नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत सामाजिक चेतना केंद्रों का प्रभावी संचालन कर वयस्कों के लिए आधारभूत शैक्षणिक गतिविधियां

संचालित करने के लिए कहा। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में समग्र आईडी एवं आधार निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा पात्र हितग्राहियों के समग्र आईडी एवं आधार प्राथमिकता से बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को समग्र आईडी, संबल पंजीयन एवं आधार जैसी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नल-जल योजनाओं एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन कराने तथा स्वास्थ्य विभाग को जलजनित बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य अमले का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नेतृत्व करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने तथा जनपद सीईओ एवं सीएमओ के साथ क्लस्टर स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना तैयार की जाए। नगरीय प्रशासन विभाग को संबंधित अमले का प्रशिक्षण आयोजित करने तथा नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने जनजातीय विकासखंडों में लर्निंग सेंटर विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करने तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) से प्रस्तावित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले में पर्यटन को लेकर ट्रेकिंग, साइक्लोथॉन एवं स्टार गेजिंग जैसे आयोजन कराने के साथ ही बैतूल टूरिज्म लोगो डिज़ाइन एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अखंड भारत के केंद्र बिंदु बरसाली के पर्यटन एवं आधारभूत विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे भारत टैक्स 2026 में निवेशकों से संवाद

● मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र को मिलेगी वैश्विक मंच पर नई पहचान

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स-2026 में देश-विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांडों से संवाद कर मध्यप्रदेश में निवेश के नए अवसरों को गति देंगे। एकल उद्योग बैठकों, राउंड टेबल चर्चा, समझौता ज्ञापनों और निवेशक संवाद के माध्यम से राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट एवं फुटवियर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। भारत टेक्ट-2026 में मध्यप्रदेश का विशेष पेवेलियन राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कौशल विकास, पीएम मित्र पार्क तथा टेक्सटाइल क्षेत्र की संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की देश-विदेश की प्रमुख टेक्सटाइल एवं गारमेंट कंपनियों के साथ प्रस्तावित एकल बैठकों में नए निवेश, उत्पादन क्षमता विस्तार, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन तथा तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस अवसर पर केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। निवेश संवर्धन, कौशल विकास, निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जनवरी 2027 में मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी और निवेश के प्रति अपनी रुचि भी व्यक्त किए जाने की संभावना है। भारत टेक्स-2026 में विशेष राउंड टेबल बैठक भी मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें टेक्सटाइल एवं गारमेंट उद्योग से जुड़े 100 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में निर्यात संवर्धन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, सतत विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और निवेश से जुड़े विषयों पर उद्योग जगत के सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार और निवेश को नई गति देने की दिशा में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों के समक्ष मध्यप्रदेश की उन विशेषताओं को भी रेखांकित करेंगे, जिसने राज्य को देश के अग्रणी टेक्सटाइल निवेश गंतव्यों में शामिल किया है। राज्य में कपास उत्पादन से लेकर स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग और गारमेंट निर्माण तक संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन उपलब्ध है। देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य के रूप में मध्यप्रदेश की पहचान, फार्म टू फैशन की अवधारणा पर विकसित हो रहा टेक्सटाइल इको सिस्टम तथा धार जिले में लगभग 2,158 एकड़ में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क वैश्विक निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। टेक्सटाइल, गारमेंट एवं फुटवियर क्षेत्र के लिए उपलब्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति, भूमि संबंधी रियायतों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं की जानकारी भी निवेशकों को दी जाएगी। भारत टैक्स-2026 के माध्यम से मध्यप्रदेश का प्रयास टेक्सटाइल क्षेत्र में नए निवेश, अधिक रोजगार, निर्यात विस्तार और दीर्घकालीन औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को जनवरी-2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागी बनने का आमंत्रण देंगे और मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर लहराया तिरंगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले युवाओं को बधाई देकर उनके उज्ज्वल एवं मंगलमय भविष्य की कामना की है। इस ओलंम्पियाड-2026 में इंदौर के प्रतिभावान छात्र श्री रिद्धेश अनंत बेंडले सहित श्री कनिष्क जैन, श्री ऋषित गर्ग, सुश्री श्रेष्ठा सुरैया और श्री स्वरित जोशी ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे युवाओं ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हम सबको आप सभी पर गर्व है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दूसरे युवाओं को भी विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

भोपाल को मिलेगी अत्याधुनिक 'अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा' की सौगात

● मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत करेंगे लोकार्पण

भोपाल (नप्र)। भोपाल के आंचलिक विज्ञान केन्द्र में विकसित अत्याधुनिक 'अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा' का लोकार्पण मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को सायं 5:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में किया जाएगा। इस अवसर पर भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, जिला प्रशासन भोपाल तथा विभिन्न वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) की इकाई आंचलिक विज्ञान केन्द्र, भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका विकास नेहरू साइंस सेंटर, मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। दीर्घा में आधुनिक डिजिटल तकनीकों, इंटरैक्टिव प्रदर्शों एवं वैज्ञानिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आगंतुकों को ब्रह्माण्ड, आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञान, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण तथा भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा से परिचित कराया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के नासदीय सूक्त और शून्य की अवधारणा से लेकर आर्यभट्ट, चंद्रयान-1, मंगलयान, चंद्रयान-3 और गगनयान जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उपलब्धियों को आकर्षक एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। दीर्घा में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अनुभव, स्पेस वॉक, स्पेस फ्लाइट सिम्युलेटर, चंद्र एवं मंगल ग्रह की त्रि-आयामी सतहों का अवलोकन, रॉकेट विज्ञान, कक्षीय यांत्रिकी सहित अनेक सहभागितापूर्ण प्रदर्श विकसित किए गए हैं, जो आगंतुकों को अंतरिक्ष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करेंगे। यह अत्याधुनिक दीर्घा विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विज्ञान प्रेमियों एवं आम नागरिकों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित के प्रति रुचि विकसित करने के साथ अनुसंधान, नवाचार एवं वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही मध्यप्रदेश में विज्ञान आधारित पर्यटन, विज्ञान संचार तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चार दिन से रुकी बारिश, उमस से लोग बेहाल

मौसम विभाग ने अगले सप्ताह जताई अच्छी बारिश की उम्मीद

बैतूल। जिले में पिछले चार दिनों से बारिश पूरी तरह थमी हुई है। बारिश रुकने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोगों के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने अगले सप्ताह जिले में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई है। दैनिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार, 10 जुलाई को जिले में केवल 0.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद 11, 12 और 13 जुलाई को जिले में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 7 जुलाई को 7.0 मिमी, 8 जुलाई को 9.6 मिमी और 9 जुलाई को 27.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी। बारिश थमने के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है। दिन का तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कम हवा और तेज धूप के कारण दिनभर चिपचिपी गर्मी महसूस की जा रही है। यदि विकासखंडवार आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो चिचोली में सबसे अधिक 431.9 मिमी, घोड़ाडोंगरी में 367.0 मिमी, मुलताई में 315.4 मिमी, भैंसदेही में 306.0 मिमी, प्रभातपट्टन में 287.6 मिमी, आमला में 277.0 मिमी, शाहपुर में 258.8 मिमी, भीमपुर में 236.0 मिमी और आठनेर में 220.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

अगले सप्ताह फिर सक्रिय होगा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह में बैतूल जिले में बारिश की गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पडने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री और न्यूनतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सप्ताह के मध्य से मानसून सिस्टम सक्रिय होने पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।

बैतूल में ट्रक पार्किंग के अभाव से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था

● ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कलेक्टर-सीएमओ से की ट्रांसपोर्ट नगर की मांग

● 600 ट्रकों के ठहराव की समस्या से जूझ रहे ट्रांसपोर्टर, कोसमी में भूमि आवंटन की मांग

बैतूल। शहर में ट्रकों के बढ़ते दबाव और पार्किंग की गंभीर समस्या को लेकर बैतूल ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कलेक्टर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि जिले में वर्तमान में 400 से 600 बड़े ट्रक संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनके व्यवस्थित ठहराव, रखरखाव तथा लोडिंग-अनलोडिंग के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है, जिससे परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि पार्किंग स्थल के अभाव में ट्रकों को मुख्य सडक़ों एवं अन्य स्थानों पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुले स्थानों पर वाहन खड़े रहने से ट्रकों और उनमें लदे माल की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। वहीं, व्यवस्थित लॉजिस्टिक्स हब नहीं होने से समय पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग में देरी होती है, जिसका सीधा असर परिवहन कार्य की कार्यक्षमता पर पड़ता है। यूनियन ने यह भी कहा कि भारी वाहनों के अव्यवस्थित संचालन से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर की मांग यूनियन कई वर्षों से लगातार उठाती आ रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन ने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में पर्याप्त शासकीय भूमि रिक्त पड़ी है, जिसे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवंटित किया जा सकता है। इससे बाहर से आने वाले भारी वाहनों का आवागमन शहर के भीतर प्रभावित किए बिना सुचारू रूप से हो सकेगा। यूनियन ने बताया कि प्रदेश के कई शहरों में इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट नगर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। यूनियन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से परिवहन कार्य अधिक व्यवस्थित होगा, शहर की यातायात व्यवस्था भी सुरक्षित और सुचारू बनेगी। साथ ही नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यूनियन ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि भूमि आवंटन के लिए शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शुल्कों का पूर्ण पालन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में यूनियन के अध्यक्ष शैलेन्द्र (संजू) राठौर, उपाध्यक्ष राजा अली, कोषाध्यक्ष मुनावर भाई, सचिव चिन्टू गौर, सूरज दुबे, दीनू पवार, मनोज तलेड़ा, दिनेश राठौर, बंटी राठौर, राजू मालवीय, राम महेश्वरी, श्याम सोनी और कमल सेनानी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

पुलिस में 185 आरक्षक बने प्रधान आरक्षक

लंबे इंतजार के बाद पदोन्नति सूची जारी

बैतूल। पुलिस विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। कुल 185 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत चयन प्रक्रिया संपन्न कर यह सूची जारी की है। जारी सूची के अनुसार, पदोन्नत होने वाले आरक्षकों में 124 अनारक्षित वर्ग से, 38 अनुसूचित जनजाति वर्ग से और 23 अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए 18 पात्र आरक्षकों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई है। इस सूची में 12 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जनजाति और 2 अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षक शामिल हैं। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध भविष्य में कोई अयोग्यता, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण या सेवा अभिलेख से संबंधित कोई विसंगति सामने आती है, तो उसकी पदोन्नति

निरस्त की जा सकती है। यह पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन भी रहेगी। इस पदोन्नति प्रक्रिया के साथ ही, पूर्व में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में जारी किए गए सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन पदोन्नति आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

पत्रकार कल्याण परिषद का अंतर संभागीय महासम्मेलन संपन्न

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए बैतूल सहित कई जिलों के पत्रकार सम्मानित

बैतूल। पत्रकार कल्याण परिषद का अंतर संभागीय महासम्मेलन हरदा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के कईयों जिलों से पहुंचे पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में पत्रकार सुरक्षा, पत्रकारों के अधिकार, संगठन की मजबूती तथा पत्रकार हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान संगठन के विस्तार की घोषणा करते हुए ऋषि कुमार त्रिपाठी को नर्मदापुरम जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर उपस्थित पत्रकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बैतूल जिला अध्यक्ष कैलाश प्रसाद अग्निहोत्री, जिला उपाध्यक्ष सुनील राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता एवं सचिव जयकिशोर मिश्रा को शाल, श्रीफल, स्मृति शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदान्ती त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ हैं। पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर कार्य कर रहा है।

बैतूल में 17-18 जुलाई को कांग्रेस का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर

संगठन सृजन अभियान के तहत दो दिन चलेगा वैचारिक मंथन

बैतूल। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत 17 और 18 जुलाई को जैन दादावाड़ी में दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा के नेतृत्व में होने वाले इस शिविर में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष भाग लेंगे। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और पदाधिकारियों को वैचारिक एवं संगठनात्मक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह आवासीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सहप्रभारी उषा नायडु और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इनके अलावा जिला प्रभारी सुनील उइके तथा प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी महेन्द्र जोशी अपनी टीम के साथ प्रशिक्षण देंगे। टीम में भूपेन्द्र पुरावत, ललित सेन, प्रोमिल मित्रा और आदित्य परिहार शामिल रहेंगे। इसके साथ ही पांचों विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी गोपालकृष्ण शर्मा, सुभाष देशमुख, आनंद राजपूत रामू टेकाम, गोविन्द व्यास, नारायणराव धोटे, हर्षवर्धन बघेल, लवलेश बब्बा राठौर, हुजैफा वोहरा और समीर खान प्रशिक्षण में शामिल होंगे। संगठन महासचिव बृजभूषण पांडे ने बताया कि 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से प्रतिभागियों का पंजीयन होगा। इसके बाद साहित्य वितरण और वंदे मातरम् तथा महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ प्रशिक्षण का शुभारंभ होगा। पहले दिन कुल सात बौद्धिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। दोपहर में भोजन अवकाश, शाम को चाय का अंतराल रहेगा। रात में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 18 जुलाई को सुबह जागरण और चाय के बाद सेवादल द्वारा झंडावंदन और व्यायाम सत्र होगा। इसके बाद दिनभर बौद्धिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोपहर भोजन अवकाश के बाद अंतिम सत्र होगा, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। आभार प्रदर्शन और राष्ट्रगान के साथ प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा।

गिट्टी के ओवरलोड और अवैध परिवहन में संलिप्त 3 वाहन जब्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खनिज विभाग बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन, ओवरलोड परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ घोड़ाडोंगरी क्षेत्रांतर्गत खनिज गिट्टी के ओवरलोड परिवहन में संलिप्त 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 04 एचई 6837 को जप्त कर पुलिस थाना घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। इसी प्रकार 13 जुलाई को खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ तहसील बैतूल अंतर्गत ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ के पास से खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 02 वाहन जॉन डियर ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 47एम 1882 एवं सोनालिका ट्रैक्टर ट्राली इंजन क्रमांक डीजेएडीएल 164729853 को जप्त कर पुलिस चौकी खेड़ीसांवलीगढ़ की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। सभी अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरणों को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

खाद्य विभाग ने आठनेर में खाद्य प्रतिष्ठानों से मसालों के 6 नमूने जांच के लिए भेजे

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन बैतूल के खाद्य सुरक्षा प्रशासन दल ने सोमवार को आठनेर के बाजार चौक स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं किराना दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री का भंडारण एवं विक्रय नहीं करने तथा नियमानुसार खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्राप्त कर ही कारोबार संचालित करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान विभिन्न दुकानों से मसालों के 6 नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। दल ने खाद्य सामग्री को ढककर रखने, प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा फलों की दुकानों पर सड़े-गले फल नहीं रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस दुकान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : कलेक्टर

पीएम आवास योजना और आंगनवाड़ी भवन निर्माण में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश

▶ कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में वीबीरामजी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास प्लस, अनुग्रह सहायता, संबल पंजीयन, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना सहित विभिन्न विकास कार्यों की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम बोरदही, खेड़ी सांवलीगढ़, हीवरखेड़ एवं भौरा में कार्ययोजना के अनुसार पशुपालन, महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित विभागों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस के अंतर्गत आवास निर्माण में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने भैंसदेही विकासखंड के ब्लॉक कॉर्डिनेटर की सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैंसदेही को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समीक्षा बैठक तक अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चिचोली, घोड़ाडोंगरी एवं भीमपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी लंबित आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने अटल ग्राम सेवा सामुदायिक भवनों के स्वीकृत कार्यों को फर्नीचर की उपलब्धता सहित शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण में विलंब पर भीमपुर के सहायक यंत्री को एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा घोड़ाडोंगरी जनपद की ग्राम पंचायत कान्हावाड़ी एवं भैंसदेही जनपद के ग्राम खामला के सरपंचों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अनुग्रह सहायता, संबल पंजीयन एवं पेंशन के लंबित प्रकरणों की भी जनपदवार समीक्षा करते हुए सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शहर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शनिवार को शहर का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में चल रहे रिनोवेशन कार्य का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्रस्तावित नवीन सर्किट हाउस के संबंध में भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह सहित हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी में प्रवेश के लिए चयन ट्रायल आयोजित

बैतूल (निप्र)। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर हमलापुर में मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी भोपाल में प्रवेश के लिए एक दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में बैतूल जिले के समस्त विकासखंडों से लगभग 50 जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। भोपाल से आए खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि श्री गोविन्द रजाक प्रशिक्षक एवं श्री जयप्रकाश यादव प्रशिक्षक ने प्रतिभागी खिलाड़ियों के शारीरिक मापदंडों, फिटनेस और जूडो खेल कौशल का बारीकी से परीक्षण किया। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को तराशना है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी, भोपाल में प्रवेश दिया जाएगा। अकादमी में चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा, आवास और डाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। प्रतिभा चयन कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा अधिकारी जनजातीय कार्य विभाग श्री विनय यादव, छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती अनिता जौधलेकर एवं समस्त प्रशिक्षक, समस्त युवा समन्वयक खेल विभाग का विशेष सहयोग रहा।

कलेक्टर के त्वरित हस्तक्षेप से छात्र कृष्णा की टीसी में हुई त्रुटि का एक ही दिन में निराकरण

विदिशा (निप्र)। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति जिला प्रशासन की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण सामने आया है। बलभद्र स्कूल, विदिशा के कक्षा दो में अध्ययनरतछात्र कृष्णा कुशवाह की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) में प्रवेश दिनांक गलत दर्ज होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशों के पालन में डीपीसी ने बिना विलंब किए बीआरसीसी को विद्यालय भेजा। मौके पर अभिलेखों का परीक्षण कर छात्र की टीसी में दर्ज प्रवेश दिनांक की त्रुटि का सुधार कराया गया। पूरी प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए छात्रा की समस्या का उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया गया। इस त्वरित कार्रवाई से छात्र एवं उसके परिजनों को राहत मिली। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि भविष्य में उनकी पढ़ाई एवं प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शैक्षणिक अभिलेख तैयार करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

विद्युत चोरी पर सख्त कार्रवाई: आरोपी को एक वर्ष का कारावास, 65,267 का जुर्माना

विदिशा (निप्र)। विद्युत चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (विद्युत), विदिशा के न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 65,267 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय को विद्युत चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, विदिशा के उपमहाप्रबंधक श्री श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (विद्युत) माननीय श्री राजेश शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक स्स्ष्श्स्स्ध 921/2022 में आरोपी शिंगराम सिंह पुत्र गबराव यादव, निवासी ग्राम विसोनिया, तहसील एवं थाना शमशाबाद, जिला विदिशा को विद्युत चोरी का दोषी पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 65,267 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालय (विद्युत), विदिशा में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए दंडादेश पारित किया।

उदयपुर के सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सत्र आयोजित

छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

विदिशा (निप्र)। छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उदयपुर स्थित सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

स्वास्थ्य शिविर के दौरान छात्राओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन, ऊंचाई तथा अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए। चिकित्सकों ने छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुना और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। जरूरतमंद छात्राओं को आगे की जांच एवं उपचार के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

परामर्श सत्र में विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, स्वच्छता, नियमित व्यायाम, एनीमिया से बचाव, मासिक धर्म स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा संक्रमण से बचाव जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छिपाने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। इस अवसर पर छात्राओं को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी पीने, नियमित दिनचर्या अपनाने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि किशोरावस्था में सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विस्तार से समाधान किया गया। छात्राओं ने इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता कार्यक्रमों को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता जताई। स्वास्थ्य विभाग एवं हॉस्टल प्रबंधन ने छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

विश्व जनसंख्या दिवस पर एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी में कार्यशाला आयोजित

बैतूल (निप्र)। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे ने बताया कि भारत शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष 11 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के मध्य विश्व जनसंख्या दिवस अभियान मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सही समय पर गर्भावस्था तथा दो बच्चों के मध्य सही समय के अंतर को स्वैच्छिक साधनों के उपयोग से बढावा देना है, जिससे मातृ मृत्यु एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ घोरे ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस संदेश को हर समुदाय तक पहुंचा कर सीमित संसाधनों और बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग छोटा परिवार अपनाकर अपना और समाज के भविष्य को बेहतर बना सके। छोटा परिवार रखने से संसाधनो का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ राजेश परिहार ने परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक लक्ष्य दम्पत्ति को परिवार नियोजन के कोई न कोई साधन से सुरक्षित करें। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस अभियान की थीम मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिये गर्भधारण के लिए सही समय तथा गर्भावस्था के मध्य सही अंतर रखा जाना जरूरी है। कार्यशाला में प्रभारी शहरी चिकित्सा अधिकारी डॉ रत्नेश खाड़े, उप जिला मीडिया अधिकारी श्री महेशराम गुबरेले, परिवार कल्याण प्रभारी श्री भगतसिंह उइके, एपीएम श्री प्रकाश माकाड़े, सुपरवाईजर श्री कृष्णा पाटिल, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

1500 रुपए के विवाद में युवक को अर्धनग्न कर पीटा

उधारी मांगने पर हुआ विवाद, डंडों से बेरहमी से मारपीट; आरोपियों का निकाला जुलूस

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के एसपीएम पुलिया क्षेत्र में 1500 रुपए के विवाद में एक युवक को अर्धनग्न कर डंडों से बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को आरोपियों को कोतवाली थाने लाने के बाद वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद कराने के लिए ग्वालटोली क्षेत्र ले जाया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। घायल युवक की पहचान शुभम खंडारे (25) निवासी एसपीएम पुलिया, ग्वालटोली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शुभम ने करीब एक साल पहले आरोपी रोहित बाबरिया और विजय रैकवार, निवासी ग्वालटोली, से 1500 रुपए उधार लिए थे। वह लंबे समय से भोपाल में रह रहा था और घटना से दो दिन पहले ही नर्मदापुरम लौटा था।

अर्धनग्न कर डंडों से बेरहमी से पीटा

8 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपियों ने शुभम से उधार के रुपए वापस मांगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दोनों युवकों ने शुभम को अर्धनग्न कर डंडों से बेरहमी से पीटा और मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद शुभम लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद कराया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

वीबी जी राम जी योजना से अब गांव में ही मिलेगा ज्यादा काम, बढ़ेगी आमदनी

सीहोर (निप्र)। ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। साथ ही, देश के किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी 300 से कम नहीं होगी, जबकि राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर लगभग 327 प्रतिदिन हो गई है।

सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के ग्राम महागांव जदीद निवासी श्रीमती कृष्णा कीर कहती हैं कि पहले रोजगार के केवल 100 दिन मिलते थे, लेकिन अब 125 दिनों तक काम मिलने से परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी। श्रीमती कृष्णा कीर ने कहा, 'यह योजना हम जैसे ग्रामीण और मजदूर परिवारों के लिए बहुत लाभकारी है। अब गांव के आसपास ही ज्यादा दिनों तक काम मिलेगा, जिससे बाहर मजदूरी के लिए कम जाना पड़ेगा। रोजाना कम से कम 300 रुपये की मजदूरी मिलने से परिवार का खर्च चलाना आसान होगा और बच्चों की पढ़ाई सहित अन्य जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देती हूं।' नई योजना में केवल रोजगार के दिनों में ही वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि ग्रामीण विकास को भी नई दिशा दी गई है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, तालाबों और खेत-तालाबों का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत संरचना का विकास, कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्य, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही समय पर रोजगार उपलब्ध कराने, निर्धारित अवधि में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने तथा कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। पहले से बने जॉब कार्ड भी मान्य रहेंगे, जिससे श्रमिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महागांव जदीद की कृष्णा कीर जैसी हजारों ग्रामीण महिलाओं और श्रमिक परिवारों के लिए वीबी जी राम जी केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत है। यह योजना विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

रिश्वत प्रकरण में नटेरन के पटवारी संदीप यादव निलंबित

विदिशा (निप्र)। लोकायुक्त भोपाल द्वारा 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए जाने के बाद तहसील नटेरन के पटवारी हल्का क्रमांक-40 (रावन) के पटवारी संदीप यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय नटेरन नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही उनके पटवारी हल्का नंबर 40 (रावन) का प्रभार श्री लेखन लोधी, पटवारी हल्का नंबर 42 (खाईखेडा) एवं पटवारी हल्का नंबर 05 (रायखेडी) का प्रभार श्री सुलभ समैया, पटवारी हल्का नंबर 06 (सकराई) को अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त तक सौपा गया है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शासकीय कन्या शाला में हुआ पौधारोपण

बैतूल (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की योजना मेरा युवा भारत बैतूल के द्वारा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत शासकीय कन्या शाला गंज बैतूल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदा प्रसाद मिश्रा, ज्योति गीद, शिक्षक महेश गुंजेले, राधेलाल बनखेडे व धनंजय सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेरा युवा भारत बैतूल के स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय परिसर में छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। पौधरोपण के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में पेड़ लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 'मेरा युवा भारत' के माध्यम से जिले भर में युवा मंडल, महिला मंडल और स्वयंसेवकों द्वारा लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी स्वयं लेने का आग्रह किया गया।

इस अवसर पर महेश गुजेले ने बताया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, छाया, फल, औषधि और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि मानव जीवन के आधार हैं। राधेलाल बनखेडे ने अपने संबोधन में जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण को एक-दूसरे से जोड़ते हुए कहा कि यदि हम पेड़ बचाएंगे तभी जल बचेगा और जीवन बचेगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम के दौरान मेरा युवा भारत पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। पोर्टल के माध्यम से युवा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों, प्रशिक्षण और सेवा कार्यों से जुड़कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में शिक्षक सुरेश बनकर, सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

अब प्रत्येक गुम इंसान प्रकरण में अनिवार्य रूप से दर्ज होगी एफआईआर

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों को प्रत्येक गुम इंसान (महिला एवं पुरुष) के प्रकरण में अनिवार्य रूप से एफआईआर पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वाराबचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकारप्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार गुम नाबालिग बच्चों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई थी।

एसडीएम-तहसीलदार ने किया कालियदेव झरने का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। इछावर एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा, तहसीलदार सुश्री अनामिका चतुर्वेदी सहित राजस्व, पुलिस एवं जनपद के अधिकारियों द्वारा कालियादेव वॉटरफॉल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने झरना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और वॉटरफॉल पर आमजन के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का पूर्णत: और सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विश्व पेपर बैग दिवस 2026 पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा द्वारा सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधि के अंतर्गत 14 एमपी बटालियन एनसीसी, विदिशा के सहयोग से विश्व पेपर बैग दिवस 2026 का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की थीम थी 'एकल-उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता फैलाना।' कार्यक्रम का आयोजन 14 एमपी बटालियन एनसीसी, विदिशा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अंशुभान सिंह के मार्गदर्शन में तथा प्रभारी प्राचार्य डॉ. मलखान सिंह,

एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट (डॉ.) विनीता प्रजापति एनसीसी कैडेट्स एवं महाविद्यालय स्टॉफ की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर प्लास्टिक को ना कहें और कागज को शानदार बनाएं' के संदेशों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से नागरिकों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन एवं 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने अनुपयोगी एवं पुनर्चक्रित सामग्री से पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, वॉल हैंगिंग आदि आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएँ बनाकर अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट (डॉ.) विनीता प्रजापति ने पर्यावरण संरक्षण विषय पर प्रेरणादायी व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों से दैनिक जीवन में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग छोड़कर पेपर बैग, कपड़े , जूट के बैग एवं अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे प्रयासों से भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय स्टॉफ एवं एनसीसी कैडेट्स ने प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण हेतु अधिकाधिक पेपर बैग के उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव कार्य करने की सामूहिक शपथ ली।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना करें तैयार: मंत्री पटेल

कचरा संग्रहण, निष्पादन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाएं स्पष्ट नीति

भोपाल (नप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की साधारण सभा की बैठक में कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि सतत जनभागीदारी और सुव्यवस्थित प्रबंधन का विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण एवं निष्पादन के लिए स्पष्ट नीति तैयार की जाए तथा पंचायतों, ब्लॉक स्तर और क्लस्टर स्तर पर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए तथा अगले 20 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कचरा निष्पादन प्रबंधन के उपाय करें। उन्होंने कचरा परिवहन के लिए वाहनों, एजेंसियों और संचालन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने पर बल दिया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को क्लस्टर आधारित स्वच्छता व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा डस्टबिन के प्रभावी उपयोग, वॉश ऑन व्हील्स मॉडल, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और गोबर-धन परियोजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सीएसआर मद का उपयोग कचरा निष्पादन इकाइयों के विकास में करने, मल-कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने तथा खुले में कचरा डंपिंग की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भुगतान व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एक अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए जा चुके हैं तथा राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में कचरा प्रबंधन के लिए वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वॉश ऑन व्हील्स अभियान के अंतर्गत 1,924 क्लस्टरों में कार्य संचालित हैं तथा 9 हजार से अधिक पानी की टंकियों की सफाई की जा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, गोबर-धन परियोजना तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

15 से 30 जुलाई तक विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए किया जाएगा जागरूक

भोपाल (नप्र)। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देंगे। अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2026 को होगी। जागरूकता रैली, ड्रग अवेयरनेस रन की गतिविधियां होंगी। इस दौरान स्थानीय मीडिया के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे तथा नशा मुक्ति से जुड़े पम्पलेट वितरित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता के लिए रील्स एवं शॉर्ट फिल्म निर्माण तथा उनका प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही नशा मुक्ति विषय पर विशेष व्याख्यान और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन आयोजित होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के आसपास तम्बाकू, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं हो, इस संबंध में भी जागरूकता सुनिश्चित की जाएगी। चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी नशा मुक्ति का संदेश देंगे। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करना है।

ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी, 3 की मौत

मुरैना में मंदिर से घर लौट रहे थे, 5 घायलों में 3 की हालत गंभीर

मुरैना (नप्र)। मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में पत्थर लोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और दो पुरुषों समेत तीन की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। ऑटो में कुल 8 लोग सवार थे। 5 लोग घायल हैं। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक ये लोग बानमौर विजय पुरा से माता बसैया के पास स्थित भूमिया बाबा मंदिर दर्शन के लिए गए थे। लौटते समय पारासर की तेवरिया के पास हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही माता बसैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। माता बसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर के अनुसार हादसा सुबह साढ़े 10 बजे हुआ। ड्राइवर को छोड़ ऑटो सवार सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं।

हादसे में इनकी मौत हुई

महेंद्र पुत्र बाबू लाल राठौर (50)
मनोरमा पत्नी राजेंद्र राठौर (45)
रामकेश पिता देवीराम कुशवाह
हादसे में 5 घायल, 3 गंभीर
सूरज पुत्र महेंद्र राठौर (24)

वंशिका पुत्री राहुल (2)
गुंजन पुत्री भूरा राठौर (11)
अंजलि पत्नी सूरज राठौर (21)
मीना पत्नी रामकरण राठौर (45)

इंदौर-रतलाम फोरलेन पर डिवाइडर से टकराई कार, डॉक्टर की मौत- रतलाम-इंदौर फोरलेन पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में रतलाम के बाल चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. मनीष सिंह और उनके 80 वर्षीय ससुर शिवनारायण राजौरिया की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब परिवार भोपाल से रतलाम लौट रहा था। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना सामने आई है।जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार रात करीब 3:30 बजे धराड़ के आगे और टोल नाके से पहले एक छोटी पुलिया के डिवाइडर से हुआ। एमजी हेक्टर कार डॉ. मनीष सिंह के साढू अजय गुप्ता चला रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

डॉक्टर परिवार के साथ लौट रहे थे- डॉ. मनीष सिंह अपनी पत्नी स्टेफनी गुप्ता, दो बच्चों रैना और सयाना (7), साढू अजय गुप्ता, उनकी पत्नी लवलीना गुप्ता और अपने 80 वर्षीय ससुर शिवनारायण राजौरिया के साथ भोपाल से रतलाम लौट रहे थे। हादसे के बाद टोल नाके की एंबुलेंस और बिलपांक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक उपनिरीक्षक समसु गरवाल ने टीम के साथ घायलों को बाहर निकालकर रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

डॉक्टर की मौके पर, ससुर की इलाज के दौरान मौत- अस्पताल में डॉक्टरों ने 42 वर्षीय डॉ. मनीष सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल उनके ससुर शिवनारायण राजौरिया ने सोमवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल अन्य परिजनों का इलाज जारी है।

रायसेन में अनाज कारोबारी के घर 1 करोड़ की चोरी

- गुना से दबोचे गए अंतरराज्यीय गैंग के 2 शातिर, राजस्थान-गुजरात तक फैले तार

रायसेन (नप्र)। जिले में पुलिस ने बरेली कस्बे में एक अनाज कारोबारी के घर हुई करीब 1 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवरों की सनसनीखेज चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गुना जिले के धार्नाओदा थाना क्षेत्र के खेजरा चक गांव से हुई है।

यह वारदात बीती 5 जुलाई की रात को बरेली

कस्बे में रहने वाले अनाज व्यापारी राजेंद्र वर्मा के घर पर हुई थी। यह इलाका जिला मुख्यालय से करीब 88 किलोमीटर दूर है। वारदात के बाद से ही पुलिस की कई टीमें चोरों की तलाश में जुटी थीं।

टेक्निकल इनपुट और फॉरेंसिक सबूतों से मिला सुराग- शिकायत दर्ज होने के बाद रायसेन पुलिस ने सायबर सेल, टेक्निकल इनपुट और घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस को सटीक मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गुना जिले के एक गांव में छिपे हैं। इसके बाद पुलिस ने फौरन रेड मारकर दो संदिग्धों को दबोच लिया।

हालांकि, पुलिस के हाथ अभी तक चोरी गए जेवर नहीं लगे हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस गिरोह का सरगना सारा माल समेटकर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

पूछताछ में खुले बड़े राज- पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि इस वारदात में उनके दो और साथी शामिल थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जाल बिछा दिया है। जांच में सामने आया है कि इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। पकड़े गए बदमाशों पर एमपी, यूपी, राजस्थान और गुजरात में चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।रायसेन पुलिस को भरोसा है कि रिमांड के दौरान इन बदमाशों से जिले में हुई दो दर्जन से ज्यादा बड़ी चोरियों का खुलासा हो सकता है।

भिंड में सीएम के हेलीकॉप्टर की उड़ान ड्रोन से रुकी

टेकऑफ से पहले हेलीपैड पर उड़ाया, यूट्यूबर हिरासत में

भिंड (नप्र)। भिंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दंदरौआ धाम यात्रा के दौरान रविवार शाम सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। मुख्यमंत्री दर्शन के बाद ग्वालियर लौटने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके थे। उनके साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया भी मौजूद थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेकऑफ की तैयारी में था, तभी हेलीपैड के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। ड्रोन देखते ही पायलट ने सुरक्षा कारणों से उड़ान भरने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़ा रहा। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने पूरे परिसर में तलाश शुरू की। जांच के दौरान मंदिर की छत पर राघवेंद्र खेमरिया नाम का युवक ड्रोन उड़ाते मिला। पुलिस ने तत्काल ड्रोन नीचे उतरवाकर उसे हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला मिहोना थाना पुलिस को सौंपा गया है।

मंदिर गतिविधियों के वीडियो बनाता है

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राघवेंद्र खेमरिया मंदिर से जुड़े वीडियो और फोटो अपने निजी यूट्यूब व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति के कुछ लोगों की पहल पर उसे सुरक्षा घेरे के भीतर प्रवेश मिला था। मुख्यमंत्री जब मंदिर में पूजा-अर्चना कर महंत रामदास महाराज से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान वह परिसर में मौजूद रहकर मोबाइल और ड्रोन कैमरे से पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहा था।

उज्जैन में प्लास्टिक गोदाम में कई घंटे तक सुलगती रही आग

शॉर्ट सर्किट की आशंका, 5 दमकल आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, 28 टैंकर मौके पर थे

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन जिले के बड़नगर में रविवार-सोमवार दरमियानी रात बारदान और प्लास्टिक से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए बड़नगर और उज्जैन की पांच दमकल मौके पर हैं और पानी लेकर 28 टैंकर पहुंचे हैं। इसके बाद भी 13 घंटे से आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।

घटना उज्जैन रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित विक्रम ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम की है। गोदाम संचालक नरपत सिंह के मुताबिक, रात करीब 12 बजे आग लगी। उन्हें करीब दो घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। तब तक गोदाम का बड़ा हिस्सा जल चुका था। गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका है और पेट्रोल पंप भी है। जिस वजह से प्रशासन आग को लेकर चिंतित है।

रात करीब 3 बजे दमकल को सूचना दी

गई। इसके बाद से अब तक 5 दमकल वाहन आग बुझाने में लगे हैं। आग लगातार फैलने के कारण उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका है।

एक करोड़ से ज्यादा का नुकसान- गोदाम संचालक ने बताया कि आग से अब तक एक करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। आग के कारण गोदाम की दीवार भी कमजोर हो गई है, जिसे गिराने की तैयारी की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके।

शॉर्ट सर्किट की आशंका

शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। हालांकि, आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है।

दोस्ती या सियासी जुगलबंदी ?

राजनीति के अखाड़े में 'स्थायी दोस्त या दुश्मन' ढूँढना वैसा ही है, जैसे रेगिस्तान में पानी तलाशना। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्गी-कैलाश की जुगलबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। दिग्विजय सिंह ने अयोध्या पदयात्रा की घोषणा की, तो कैलाश विजयवर्गीय का दिल पसीज गया। उन्होंने न केवल दिग्विजय को ब्रिलियंटव इंटेलीजेंट बताया, बल्कि 80 वर्ष की उम्र में उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी करार दे दिया। दिग्विजय ने भी कभी तपाक से कैलाश जी को कलाकार जी कहकर पलटवार किया था। दिग्विजय सिंह द्वारा कभी आरएसएस की तारीफ पर कैलाश का कायल होना यह आपसी सम्मान है या तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी का सियासी खेल? जनता सोच रही है कि ये राजनेता हैं या जुगलबंदी के मंझे हुए कलाकार!

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

दतिया में 'कटिंग' का साइड इफेक्ट

दतिया उपचुनाव के टिकट वितरण ने न केवल हलचल मचा दी है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों की कलई भी खोल दी है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर आशुतोष तिवारी का नाम आगे आना, पार्टी के मिशन अनुशासन का हिस्सा है या किसी नए पावर सेंटर को पनपने से रोकने का जतन? राजनीतिक पंडितों की मानें तो यह सिर्फ जीतने की संभावना का सवाल नहीं था, बल्कि भाषा और व्यवहार की मर्यादा लांघने का दंड भी था। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान उस अपशब्द संस्कृति से तंग आ चुका था। अब नामांकन के दिन पूर्व मंत्री जी का भावुक होना और घर-घर शीश नवाऊँगा का नारा देना, सहानुभूति बटोरने की आखिरी कोशिश है या वाकई प्रायश्चित? खैर, जनता तो कटिंग के बाद का स्वाद उपचुनाव के नतीजों में ही चखेगी।

उनके आँसू और उनकी हँसी...

दतिया के भाजपा एकजुटता मंच की सभा में नरोत्तम के आँसुओं ने एक भावुक पल पैदा कर दिया। लेकिन जिस वक्त नरोत्तम बाबू की आँखों से आँसू निकल रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री उन्हें संभाल रहे थे, ठीक उसी समय पीछे बैठीं-जिनका कभी नरोत्तम से 36 का आंकड़ा हुआ करता था-एक नेत्री गुफ्तगू करते हुए हँस रही थीं। कैमरामैनों की नजर जैसे ही उन पर गई, आँसू और हँसी एक साथ वीडियो में कैद हो गए और यह चर्चा सोशल मीडिया की स्क्रीन पर आम हो गई। लोग कह रहे हैं कि यह सब वक्त का फेर है; जो कभी नरोत्तम से आँख नहीं मिला पाते थे, वे आज उनकी आँखों में आँसू देखकर दिल में ठंडक महसूस कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की 'ए-प्लस' फाइलें और...

सरकार के मुखिया की ए-प्लस नोटशीट का हाल बयाँ करना... जाने दो यार! चार बार हिदायत देते हुए रात 8 बजे की डेडलाइन तय की गई, लेकिन विभाग हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। स्कूल शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक, फाइलों की चाल कछुए से भी सुस्त है। ऐसा लगता है कि बाबुओं की मेजों पर रखी ये ए-प्लस फाइलें अब किसी सरकारी आदेश का इंतज़ार नहीं कर रहीं, बल्कि शायद कचरे के डिब्बे की रद्दी बनने की राह देख रही हैं। सवाल यह है कि क्या मुखिया का आदेश सिर्फ कागजी रस्म अदायगी है, या वाकई उनके दरबार में अधिकारियों ने सुनना ही बंद कर दिया है? अब देखना यह है कि ये फाइलें बाहर निकलती हैं या फाइलों के अंदर ही दम तोड़ देती हैं।

धार भोजशाला मामले पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली/भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें इस विवादित परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने मुस्लिम पक्ष ने इस मामले पर बेहद जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी।

सीजेआई ने कहा याचिकाओं की कमियों को दूर करें- मामले की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी और वकील निज़ाम पाशा ने अदालत से इसे तुरंत सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकीलों को याचिकाओं में मौजूद तकनीकी कमियों को फौरन दूर करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष (याचिकाकर्ताओं) की ओर से कई याचिकाएं एक साथ (समूह में) दायर की गई हैं।

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने किया नामांकन

जीतू पटवारी ने कहा- 25,000 वोटों से होगी हमारी जीत

दतिया (नप्र)। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह से दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। उनके नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। घनश्याम सिंह दतिया विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है।

घनश्याम सिंह ने किया नॉमिनेशन- घनश्याम सिंह के नॉमिनेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी भी वहां मौजूद रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के मैदान से हटने के बाद दतिया का मुकाबला आसान हो गया है।

हमें खुशी है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला- पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दतिया में कहा कि हमें खुशी है कि हमारे हमलों की वजह से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जो अत्याचारी और अन्यायपूर्ण हैं और जिनका स्वभाव रावण जैसा है। उन्होंने कहा कि अब जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, उसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के घोटाले के दौरान नरोत्तम मिश्रा के साथ पैसों के लेन-देन में उसका नाम सामने आया था। इसलिए उस पर पैसों की गड़बड़ी का आरोप है।

25000 वोट से जीतने का दावा- वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का अवसर दतिया को मिला है। दतिया की जनता इस अवसर को भुनाएगी। फिर से दतिया में बीजेपी को कम से कम 25,000 वोटों से हराएगी। वहीं, नरोत्तम मिश्रा के मामले में कहा कि यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया में कांग्रेस एकजुट है।

गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती को जीत मिली थी। लोन फ्रॉड केस में सजा होने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई।

मुख्यमंत्री ने श्रीमती गंगा मकवाणा के निधन पर शोक व्यक्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा की माताजी श्रीमती गंगा मकवाणा के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।